RNI No. MPHIN/2015/64451 डाक पंजीयन क्र. MP/IDC/1525/2019-2021 IPT डाक द्वारा प्रेषण प्रति शुक्रवार indianplasttimes@gmail.com

www.Indianplasttimes.in

इंडियन प्लास्ट टाइम्स

INDORE 03 FEBRUARY TO 09 FEBRUARY 2021 प्रति बुधवार वर्ष 06 अंक 24 पृष्ठ 8 कीमत 5 रु.

Inside News

Sensex पहली बार 50,000 अंक के ऊपर हुआ बंद Page 2

बेंगलुरु एयर शो में दुनिया देख रही भारत की ताकत का 'तेज' Page 3

भारतीय बाजार में फ्रेंच कार Citroen C5 Aircross की एंट्री Page 7

editoria!

मुश्किलें और जरूरत

संसद में केंद्रीय बजट के जरिए अर्थव्यवस्था को बल देने की जो कोशिशें हुई हैं, उनका जमीनी असर न केवल योजनाओं और बजट के क्रियान्वयन, बल्कि सरकार के भावी निर्णयों पर निर्भर करेगा। जो प्रयास मूलभूत ढांचे में निवेश या उद्योग जगत को प्रोत्साहित करने के लिए किए गए हैं, उनसे हम उम्मीद कर सकते हैं। बजट से भी जाहिर है, सरकार लोगों को मिल रही प्रत्यक्ष आर्थिक मदद के अभी तक के प्रयासों से संतुष्ट है और इसका बखान बजट में बखूबी हुआ है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में आत्मनिर्भर भारत पर जोर दिया है, तो कोई आश्चर्य नहीं। कोविड-19 महामारी का मुकाबला करने के लिए सरकार के 27.1 लाख करोड़ रुपये के आत्मनिर्भर भारत पैकेज से संरचनात्मक सुधारों को बढ़ावा मिला है। अब आम बजट में सरकार ने 64,180 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ आत्मनिर्भर स्वास्थ्य कार्यक्रम शुरू करने का प्रस्ताव रखा है। स्वास्थ्य ढांचा मजबूत करना कितना जरूरी है, यह हमने कोरोना के समय अच्छी तरह समझ लिया है। इसके अलावा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन भी जारी रहेगा। बहरहाल, जब सरकारी खजाना दबाव में है, तब आयकरदाताओं को वैसे भी राहत की ज्यादा उम्मीद नहीं थी। सरकार ने 75 साल या उससे अधिक उम्र के पेंशनभोगियों को कुछ राहत दी है। 135 करोड़ लोगों के देश में करीब छह करोड़ लोग आयकर रिटर्न दाखिल करते हैं, जबकि करीब तीन करोड़ लोग ही आयकर चुकाते हैं। मुश्किल समय में सरकार आयकर का दायरा बढ़ाने के लिए कुछ कर सकती थी। यह आयकर बढ़ाने का समय नहीं है, यह अन्य करों को बढ़ाने का भी समय नहीं है। ऐसे में, सरकार ने पेट्रोल पर 2.5 रुपये प्रति लीटर का अधिभार लगाया है, जबकि डीजल पर 4 रुपये। इससे पेट्रोल, डीजल की कीमतों को तीन अंकों में जाने और बने रहने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा, मतलब महंगाई बढ़ेगी। मोबाइल उपकरण पर कस्टम ड्यूटी बढ़ेगी, लेकिन इसका लाभ तभी है, जब देशी कंपनियां स्वयं पर्याप्त उपकरण बनाने लगें, वरना आज के समय में मोबाइल फोन को महंगा करने की दिशा में कोई भी निर्णय अनुकूल नहीं है। जब भारत को निर्यात बढ़ाने के लिए ज्यादा प्रयत्न करने हैं, तब आयात बढ़ाने के छोटे-मोटे उपाय भले किसी निजी कंपनी या उपभोक्ता के लिए फायदेमंद हों, लेकिन हमें व्यापकता में देश की आत्मनिर्भरता बढ़ाने के बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। सस्ते घर की सुविधा, डूबते कर्ज का प्रबंधन, सरकारी बैंकों को पूंजी देने का प्रस्ताव, उज्ज्वला योजना का विस्तार, रेल व बस सेवा विस्तार, किसानों को फसल लागत से डेढ़ गुना मूल्य देने का इरादा इत्यादि अनेक प्रशंसनीय कोशिशें हैं। हम समझ सकते हैं, विनिवेश से भी सरकार पैसे जुटाना चाहती है, यह पुराना एजेंडा है। पिछले बजट में 2.1 लाख करोड़ रुपये विनिवेश से जुटाने का अनुमान था और इस बार 1.75 लाख करोड़ रुपये जुटाने का इरादा है, लेकिन यह एक ऐसा मोर्चा है, जहां सरकार को राजनीति और अनेक अड़चनों का सामना करना पडेगा। ग्रामीण विकास, रोजगार और सामाजिक क्षेत्र में सरकार के खर्च का बढ़ना तय है, अतः सरकार को इस दौर में वित्तीय घाटे की चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। यह ज्यादा व सुनियोजित खर्च के साथ अर्थव्यवस्था में मांग और विकास की गति बढ़ाने का समय है।

बजट से अब तक सरकार को मिल चुकी है 3 बड़ी खुशखबरी

नई दिल्ली। एजेसी

देश के निर्यात में जनवरी महीने में बढ़ोत्तरी हुई है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, देश के निर्यात में जनवरी, 2021 में 5.37 फीसदी की बढ़ोत्तरी हुई है। इस बढ़त से जनवरी में निर्यात बढ़कर 27.24 अरब डॉलर हो गया। मंत्रालय ने बताया कि जनवरी में हुई निर्यात में वृद्धि में मुख्य रूप से फार्मास्युटिकल और इंजीनियरिंग क्षेत्र का योगदान रहा। आंकड़ों के अनुसार, जनवरी, 2021 में आयात में भी बढ़ोत्तरी दर्ज की गई। इस दौरान देश का आयात 2 फीसदी बढ़कर 42 अरब अमरीकी डालर हो गया। इस प्रकार समीक्षाधीन अवधि में देश का व्यापार घाटा 14.75 अरब अमरीकी डालर का रहा है।

फार्मा और इंजीनियरिंग में जोरदार तेजी

आकंड़ों के अनुसार, जनवरी महीने में फार्मास्युटिकल्स का और इंजीनियरिंग क्षेत्र का निर्यात क्रमशः 16.4 फीसदी और 19 फीसदी बढ़ा। इससे पहले दिसंबर, 2020 में भी निर्यात में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई थी। दिसंबर, 2020 में निर्यात मामूली बढ़कर 27.15 अरब डॉलर पर पहुंचा था। इस दौरान आयात 7.56 फीसदी बढ़कर 42.59 अरब डॉलर रहा था. इस तरह दिसंबर, 2020 में व्यापार घाटा बढ़कर 15.44 अरब डॉलर पर रहा था। इस तरह जनवरी, 2021 में देश के व्यापार घाटे में दिसंबर, 2020 की तुलना में गिरावट आई है।

निर्यात 27 बिलियन डॉलर के पार

दिसंबर 2019 में निर्यात 27.11 बिलियन डॉलर रहा था, जबकि आयात 39.5 बिलियन डॉलर रहा था। वहीं, नवंबर 2020 में निर्यात में 8.74 फीसद की गिरावट रही थी। मौजूदा वित्त वर्ष में अप्रैल से दिसंबर के दौरान, देश के माल निर्यात में 15.8 फीसदी की गिरावट रही है, जिससे यह 200.55 बिलियन डॉलर रहा.

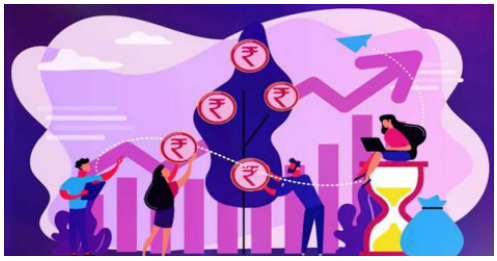

जबकि वित्त वर्ष 2019-20 की समान अवधि में यह 238.27 बिलियन डॉलर रहा था।

जीएसटी के मोर्चे पर भी खुशखबरी

इससे पहले जनवरी महीने में जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड तेजी आई है। जनवरी महीने में कुल जीएसटी कलेक्शन 1.20 लाख करोड़ रुपए पर पहुंच गया था। मंत्रालय ने कहा कि यह पिछले पांच महीनों में जीएसटी राजस्व संग्रह के रुख के अनुरूप है। जनवरी 2021 में जीएसटी संग्रह साल भर पहले की तुलना में आठ प्रतिशत अधिक है। वित्त मंत्रालय ने एक बयान में कहा, 'जनवरी 2021 में 31 तारीख की शाम छह बजे तक जीएसटी राजस्व संग्रह 1,19,847 करोड़ रुपए रहा। इसमें केंद्रीय जीएसटी (ण्डएऊ) 21,923 करोड़ रुपए, राज्यों का जीएसटी (एडएऊ) 29,014 करोड़ रुपए, एकीकृत जीएसटी (ष्ठएऊ) 60,288 करोड़ रुपए (सामानों के आयात से प्राप्त 27,424 करोड़ रुपए) और सेर 8,622 करोड़ रुपए (माल के आयात पर एकत्र 883 करोड़ रुपए सहित) शामिल है.' जीएसटी बिक्री रिटर्न दाखिल करने की अधिक संख्या के कारण यह आंकड़ा और अधिक हो सकता है।

फिर सस्ता हुआ सोने-चांदी का भाव

नई दिल्ली। सोने की कीमत में गिरावट का दौर जारी है। आज भी सर्राफा बाजार में सोने-चांदी में गिरावट देखने को मिला है। ज्वेलरी खरीदने का अच्छा समय चल रहा है, लगातार कीमतों में गिरावट हो रही। सरकार ने सोने-चांदी पर कस्टम ड्यूटी घटाने का ऐलान किया तो सोने की चमक फीकी पड़ गई। सोने का भाव 48000 रुपए के आंकड़े को पार है, वहीं चांदी की कीमत 67000 रुपए के आंकड़े को पार कर गई।58 रु की गिरावट के साथ 47976 रुपये पर बंद हुआ सोना सोमवार को 2 फरवरी को सोना 48364 पर बंद हुआ था। आज 3 फरवरी को देशभर के सर्राफा बाजारों में सोमवार को 24 कैरेट सोने का हाजिर भाव 330 रुपये प्रति 10 ग्राम सस्ता होकर 48,034 रुपये पर खुला। वहीं दिनभर में सोना आज 58 रु की गिरावट के साथ 47976 रुपये पर बंद हुआ। 311 रु की गिरावट के साथ 67496 रु पर बंद हुई चांदी बात करें चांदी कि तो 2 फरवरी को चांदी 70302 पर बंद हुई थी। वहीं आज 3 फरवरी को जबकि चांदी के भाव में 2,495 रुपये की गिरावट के सा 67,807 रुपये पर खुली। जबकि शाम को 311 रु की गिरावट के साथ 67496 रु पर बंद हुई। बता दें इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन द्वारा जारी इस रेट और आपके शहर के भाव में 500 से 1000 रुपये का अंतर आ सकता है।सोने-चांदी के हाजिर भाव इस प्रकार देशभर के सर्राफा बाजार पर एक नजर इंडिया बुलियन एंड ज्वैलर्स एसोसिएशन की वेबसाइट (ibjarates.com) पर जारी किए गए रेट के मुताबिक आज 24 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत 48034 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। वहीं 23 कैरेट शुद्धता वाले सोने की कीमत में 47842 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई, वहीं 22 कैरेट वाले सोने की कीमत 43999 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई तो 18 कैरेट वाले सोने की कीमत 36026 रुपए प्रति 10 ग्राम हो गई। वहीं चांदी की कीमत 67807 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई।सोने की मांग 35 प्रतिशत घटी देश की सोने की मांग बीते साल यानी 2020 में 35 प्रतिशत से अधिक घटकर 446.4 टन रह गई। विश्व स्वर्ण परिषद (डब्ल्यूजीसी) की एक रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। डब्ल्यूजीसी की 2020 की सोने की मांग के रुख पर रिपोर्ट में कहा गया है कि कोरोना वायरस की वजह से लागू लॉकडाउन और बहुमूल्य धातुओं के दाम अपने सर्वकालिक उच्चस्तर पर पहुंचने के बीच सोने की मांग में गिरावट आई। डब्ल्यूजीसी के आंकड़ों के अनुसार बीते साल मूल्य के हिसाब से सोने की मांग में 14 प्रतिशत की गिरावट आई और यह घटकर 1,88,280 करोड़ रुपये रह गई। 2019 में मूल्य के हिसाब से सोने की मांग 2,17,770 करोड़ रुपये रही थी।

महंगे होंगे मोबाइल फोन, सरकार ने पुर्जों, चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाया

नयी दिल्ली। सरकार ने मोबाइल फोन के पुर्जों तथा चार्जर पर आयात शुल्क बढ़ाने का फैसला किया है। स्थानीय मूल्यवर्धन को बढ़ाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। इससे मोबाइल फोन महंगे हो सकते हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2021-22 का आम बजट पेश करते हुए सीमा शुल्कों में 400 रियायतों की समीक्षा की घोषणा की। इनमें मोबाइल उपकरण खंड भी शामिल है। सीतारमण ने कहा, ''घरेलू मूल्यवर्धन बढ़ाने के लिए हम मोबाइल के चार्जर और कुछ पुर्जों पर छूट को वापस ले रहे हैं। इसके अलावा मोबाइल के कुछ पुर्जों पर आयात शुल्क शून्य से 2.5 प्रतिशत हो जाएगा।'' उन्होंने कहा कि सीमा शुल्क नीति का दोहरा उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को प्रोत्साहन देना और भारत को वैश्विक मूल्य श्रृंखला से जोड़ना तथा निर्यात को बेहतर करना होना चाहिए। सीतारमण ने कहा, ''अब हमारा जोर कच्चे माल तक आसान पहुंच तथा मूल्यवर्धन का निर्यात है।''

Sensex पहली बार 50,000 अंक के ऊपर हुआ बंद

मुम्बई। एजेंसी

बुधवार यानी 3 फरवरी 2021 को शेयर बाजार भारी तेजी के साथ बंद हुआ। आज जहां सेंसेक्स करीब 458.03 अंक की तेजी के साथ 50255.75 अंक के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 142.10 अंक की तेजी के साथ 14790.00 अंक के स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स आज पहली बार 50,000 अंक के स्तर पर बंद होने में सफल रहा है। इससे पहले यह इंट्राडे में 50000 अंक के स्तर के ऊपर निकला तो था, लेकिन बंद नहीं हो सका था। इसके अलावा आज बीएसई में कुल 3,141 कंपनियों में ट्रेडिंग हुई, इसमें से करीब 1,790 शेयर तेजी के साथ और 1,196 शेयर गिरावट के साथ बंद हुए। वहीं 155 कंपनियों के शेयर के दाम में कोई अंतर नहीं आया। वहीं आज शाम को डॉलर के खिलाफ रुपया बिना किसी घटबढ़ के 92.96 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप गेनर इंडसइंड बैंक का शेयर करीब 73 रुपये की तेजी के साथ 1,048.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। पॉवर ग्रिड कार्पोरेशन का शेयर करीब 12 रुपये की तेजी के साथ 206.50 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। कोल इंडिया का शेयर करीब 6 रुपये की तेजी के साथ 137.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। डा रेड्डी लैब का शेयर करीब 167 रुपये की तेजी के साथ 4,649.55 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। देवी लैब का शेयर करीब 132 रुपये की तेजी के साथ 3,680.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी के टॉप लूजर श्री सीमेंट का शेयर करीब 438 रुपये की गिरावट के साथ 25,994.40 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। यूपीएल का शेयर करीब 8 रुपये की गिरावट के साथ 558.25 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। मारुति सुजुकी का शेयर करीब 66 रुपये की गिरावट के साथ 7,589.20 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। अल्ट्रा टेक सीमेंट का शेयर करीब 49 रुपये की गिरावट के साथ 6,074.70 रुपये के स्तर पर बंद हुआ। आईटीसी का शेयर करीब 1 रुपये की गिरावट के साथ 216.75 रुपये के स्तर पर बंद हुआ।

अदाणी टोटल गैस लिमिटेड के वित्त वर्ष 21 की तीसरी तिमाही के परिणाम

परिचालन से प्राप्त राजस्व 522 करोड़ रुपये, सीएनजी स्टेशन बढ़कर 151 हुए

अहमदाबाद। आईपीटी नेटवर्क

भारत में गैस यूटिलिटी सेक्टर में भारत की अग्रणी निजी कंपनियों में से एक, अदाणी टोटल गैस लिमिटेड ('एटीजीएल') ने आज 31 दिसंबर 2020 को समाप्त हुई तीसरी तिमाही के लिए वित्तीय और परिचालनप्रदर्शन की घोषणा की। 30 सितम्बर 20 को समाप्त हुई तिमाही के दौरान, कंपनी को वित्त वर्ष 2008-09 से संबंधित गैस कनेक्शन आय पर सेवा कर देयता के संबंध में भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय से 28 अगस्त 2020का एक आदेश प्राप्त हुआ।

कंपनी के तिमाही परिणाम पर टिप्पणी करते हुए, श्री गौतम अदाणी, चेयरमैन, अदाणी ग्रुपने कहा कि 'मैं अदाणी और टोटल के संयुक्त तालमेल के कारण हासिल की गई प्रगति का गवाह रहा हूं। हमारी सामूहिक ताकत गैस आधारित अर्थव्यवस्था के निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देगी। हम एक सतत भविष्य के निर्माण करने की अपनी दृष्टि के अनुरूप देश भर में इस स्वच्छ ईंधन को ले जाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।'

अदाणी टोटल गैस के सीईओ श्री सुरेश पी. मंगलानी ने कहा कि 'दोनों प्रोमोटर पार्टनरों की प्रबल रुचि को दर्शाने के लिए कंपनी का नाम बदलकर'अदाणी टोटल गैस लिमिटेड '(एटीजीएल) कर दिया गया है। कंपनी ने जारी वैश्विक महामारी के बावजूद मजबूत भौतिक इंफ्रास्ट्रक्चर विकास करने के साथ अब तक के उच्चतम वित्तीय प्रदर्शन वाली लगातार दूसरी तिमाही दर्ज की है। हम फास्ट ट्रैक मोड पर सीजीडी इन्फ्रास्ट्रक्चर के विस्तार की रणनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। हम समाज को लगातार प्रोत्साहित कर रहे हैं कि लोग अपने वाहनों को पर्यावरण-अनुकूल सीएनजी में बदलें और कार्बन फुटप्रिंट को कम करने में योगदान दें।'

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपये की विनिमय दर स्थिर

मुंबई। एजेंसी

अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया बुधवार को स्थिर बंद हुआ। घरेलू शेयर बाजार में मजबूत रुख के बीच रुपये की विनिमय दर एक पैसे की मामूली बढ़त के साथ 72.95 (अस्थायी) पर बंद हुआ। अंतरबैंक विदेशी विनिमय बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया 72.96 पर खुला और एक समय कारोबार के दौरान ऊंचे में 72.92 और नीचे में 72.98 तक चला गया था। अंत में यह कल के बंद स्तर से केवल एक पैसे की मामूली बढ़त के साथ 72.95 पर बंद हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपया कल 72.96 पर बंद हुआ था। उधर, घरेलू शेयर बाजार में बीएसई सेंसेक्स 458.03 अंक यानी 0.92 प्रतिशत मजबूत होकर 50,255.75 अंक जबकि एनएसई निफ्टी 142.10 अंक यानी 0.97 प्रतिशत छलकर 14,789.95 अंक पर बंद हुआ।

मध्यम अवधि में प्रभावित हो सकती है भारत की राजकोषीय स्थिति : मूडीज

नयी दिल्ली। एजेंसी

रेटिंग एजेंसी मूडीज ने कहा है कि भारत का राजकोषीय घाटे का अनुमान उम्मीद से कहीं ऊंचा है। यदि अर्थव्यवस्था की मजबूती की रफ्तार सुस्त रहती है, तो मध्यम अवधि में भारत की राजकोषीय स्थिति प्रभावित हो सकती है। अमेरिकी एजेंसी ने कहा कि उसका अनुमान है कि वित्त वर्ष 2020-21 में स्थिर मूल्य पर भारत का सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) बढ़कर 17 प्रतिशत पर पहुंच सकता है। यह बजट में लगाए गए 14.4 प्रतिशत के अनुमान से अधिक होगा। मूडीज के उपाध्यक्ष विलियम फॉस्टर ने कहा कि राजकोषीय घाटे का अनुमान एजेंसी के अनुमान से अधिक है, लेकिन इससे पूर्व के वर्षों के बजट की तुलना में विश्वसनीय बजटीय आकलन और अधिक पारदर्शिता का पता चलता है। फॉस्टर ने कहा, ''बजट वद्धि को प्रोत्साहन के लिए ऊंचे पूंजीगत खर्च, वित्तीय क्षेत्र सुधार और संपत्ति की बिक्री पर केंद्रित है। लेकिन कार्यान्वयन के जोखिम कायम हैं। राजकोषीय मोर्चे पर मजबूती की रफ्तार सुस्त रहने से मध्यम अवधि में भारत की राजकोषीय स्थिति प्रभावित होगी।'' बजट में वित्त वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटे को सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) के 4.5 प्रतिशत पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि खाद्य सब्सिडी खर्च और अधिक सतर्क राजस्व आकलन की वजह से वित्त वर्ष 2020-21 में सरकार का राजकोषीय घाटा काफी ऊंचा रहने का अनुमान है। चालू वित्त वर्ष में राजकोषीय घाटा 9.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। मूडीज के नोट में कहा गया है, ''हमारा मानना है कि चौथी तिमाही में राजस्व संग्रह मजबूत रहने की वजह से अंतिम आंकड़ा इससे कहीं कम होगा।'' बजट में अगले वित्त वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा 6.8 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। मूडीज के नोट ''भारत का बजट वृहद आर्थिक वृद्धि को प्रोत्साहन देगा, पर राजकोषीय मजबूत की संभावनाएं कमजोर' में कहा गया है कि हमारा अनमान है कि 2020-21 में स्थिर मूल्य पर जीडीपी की वृद्धि 17 प्रतिशत के करीब रहेगी।'' मूडीज का मानना है कि आर्थिक परिस्थितियों में सुधार तथा वित्तीय बाजारों के समर्थन से 1.75 लाख करोड़ रुपये का विनिवेश लक्ष्य हासिल हो सकता है।

वॉचो ने भारी वृद्धि दर्ज की, 15 मिलियन यूजर्स का जश्न मनाया

इंदौर। भारत की प्रमुख डीटीएच कंपनी डिश टीवी इंडिया लिमिटेड ने घोषणा की है कि उसके ओटीटी प्लेटफॉर्म वॉचो ने हाल ही में 15 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर लिया है। अपनी अलग पहचान बनाते हुए 'वॉचो' ने अपने मौलिक और रोचक कंटेन्ट से युवाओं की जरूरतों को पूरा किया है और बेहद कम समय में यह उपलब्धि हासिल की है। डिजिटल उपभोग के लिये उपयुक्त शॉर्ट फॉर्मेट कंटेन्ट पर केन्द्रित, वॉचो दर्शकों के लिये एक तरोताजा नये प्लेटफॉर्म बनकर उभरा है। विभिन्न स्क्रीस (एंड्रॉइड और आईओएस डिवाइसेस, डिश एसएमआरटी डिवाइसेस, डी2एच मैजिक डिवाइसेस, और फायर टीवी स्टिक) और www.watcho.com पर उपलब्ध वॉचो हिंदी, कन्नड़ और तेलुगू भाषाओं में 35 से ज्यादा ओरिजिनल शोज दिखाता है। यह एक अनोखा प्लेटफॉर्म है, जो न केवल कंटेन्ट की खपत करवाता है, बल्कि डिशटीवी और डी2एच सब्सक्राइबर्स के लिये लाइव टीवी भी देता है। इसके अलावा, इस प्लेटफॉर्म ने हाल ही में अपनी यूजर-जनरेटेड कंटेन्ट पेशकश ''वॉचो स्वैग'' भी लॉन्च की है, जो कंटेन्ट क्रिएशन, लर्निंग और टैलेंट दिखाने के लिये एक अनूठा प्लेटफॉर्म प्रदान करती है। इस उपलब्धि पर अपनी बात रखते हुए डिश टीवी इंडिया लिमिटेड के एक्जीक्यूटिव डायरेक्टर और ग्रुप सीईओ श्री अनिल दुआ ने कहा, ''हमें यह घोषणा करते हुए बहुत खुशी हो रही है कि डिश टीवी इंडिया के ओटीटी प्लेटफॉर्म वॉचो ने 15 मिलियन यूजर्स का आंकड़ा पार कर एक और उपलब्धि हासिल की है। वॉचो की वृद्धि बेहतरीन रही है और 15 मिलियन का आंकड़ा पार करने में उसे केवल एक साल लगा, जनवरी 2020 में यह आंकड़ा 1 मिलियन प्ल स था। हमारा लक्ष्य हमेशा अनूठे कंटेन्ट की पेशकश करने का रहा है और यह उपलब्धि दिखाती है कि हमारी मेहनत सफल हुई। इस बेमिसाल उपलब्धि के लिये मुझे वॉचो की पूरी टीम पर गर्व है और मैं हमारे ग्राहकों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें चुना।''

GST क्षतिपूर्तिः 14वीं श्रृंखला के तहत सरकार ने राज्यों को दिए 6000 करोड़ रुपये

नई दिल्ली। एजेंसी

वित्त मंत्रालय ने राज्यों के वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) मुआवजे में कमी की भरपाई के लिए 14वीं किस्त के रूप में 6,000 करोड़ रुपये हस्तांतरित किए हैं। वित्त मंत्रालय ने बुधवार को यह जानकारी दी। 6,000 करोड़ रुपये में से 5,516.60 करोड़ रुपये 23 राज्यों को मिले हैं, वहीं 483.40 करोड़ रुपये दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर और पुदुचेरी को हस्तांतरित किए गए हैं।

अक्तूबर 2020 में केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर विपक्षी दलों द्वारा शासित राज्यों की मांग को स्वीकार कर लिया था। उनकी मांग थी कि केंद्र स्वयं कर्ज लेकर राज्यों की जीएसटी की क्षतिपूर्ति करे। वित्त मंत्रालय ने कहा कि केंद्र, राज्यों को जीएसटी संग्रह में 1.1 लाख करोड़ रुपये की कमी की क्षतिपूर्ति के लिए बाजार से किस्तों में कर्ज उठाएगा।

अगस्त में राज्यों को दिए थे दो विकल्प

मंत्रालय ने कहा था कि वह हर सप्ताह राज्यों को 6,000 करोड़ रुपये जारी करेगा।

वित्त मंत्रालय ने कहा कि इस व्यवस्था से केंद्र के राजकोषीय घाटे पर असर नहीं होगा और यह राज्य सरकारों की पूंजी प्राप्ति के रूप में प्रदर्शित होगा। केंद्र ने जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर अगस्त 2020 में राज्यों को दो विकल्प दिए थे। पहला वह जीएसटी क्रियान्वयन के कारण राजस्व संग्रह में कमी को पूरा करने के लिये 97,000 करोड़ रुपये रिजर्व बैंक की विशेष खिड़की से ले या फिर कुल 2.35 लाख करोड़ रुपये (इसमें 1.38 लाख करोड़ रुपये कोविड संकट के कारण) बाजार से ऋण ले ले। इस राशि को संशोधित कर अब क्रमशः 1.10 लाख करोड़ रुपये और 1.8 लाख करोड़ रुपये कर दिया गया है। जीएसटी संग्रह जनवरी में रिकॉर्ड 1.21 से 1.23 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान है। इससे राज्य जीएसटी संग्रह में कमी न्यूनतम 11,000 करोड़ रुपये रह जाएगी। एक रिपोर्ट में यह कहा गया है। जीएसटी संग्रह में खामियों को दूर करने के लिए किए गए प्रयासों का सकारात्मक परिणाम सामने आया है।

होटल के कमरों पर GST को लेकर सरकार ने दूर की आशंका, संसद में दी सफाई

नई दिल्ली। एजेंसी

केंद्रीय पर्यटन मंत्री प्रह्लाद पटेल ने मंगलवार को राज्यसभा में होटलों के सभी कमरों पर लगने वाली जीएसटी को लेकर संसद में सफाई दी है। उन्होंने कहा कि होटलों के कमरों पर जीएसटी को घटाकर 12 फीसदी करने के लिए जीएसटी परिषद से अनुरोध करने की कोई योजना नहीं बनाई गई है। पटेल ने राज्यसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में कहा कि मंत्रालय इस बात से अवगत है कि होटलों समेत पर्यटन की अनेक सेवाओं पर लगने वाले कर से दूसरे देशों के मुकाबले देश के पर्यटन क्षेत्र की प्रतिस्पर्धा पर सीधा असर पड़ता है। उन्होंने कहा कि इस समय पर्यटन मंत्रालय की होटलों के सभी तरह के कमरों पर जीएसटी घटाकर 12 फीसदी करने का अनुरोध करने की कोई योजना नहीं है। जीएसटी परिषद कारोबार के विभिन्न पहलुओं को प्रभावित करने वाले कारकों पर विचार करने के बाद तथा अर्थव्यवस्था के चतुर्दिक विकास के लिए जरूरी राजस्व अर्जित करने के लिए करों की दर पर फैसला करती है। पटेल ने सदन को यह भी सूचित किया कि पर्यटन मंत्रालय ने जीएसटी के विषय को समय-समय पर वित्त मंत्रालय के साथ उठाया है और इस क्षेत्र के लिए जीएसटी के चरणों में कुछ बदलाव किए गए हैं।

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक दो महीनों में जुटाएंगे 10,000 करोड़ रुपयेः वित्तीय सेवा सचिव

नयी दिल्ली। एजेंसी

सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक (पीएसबी) कर्ज की बढती मांग और नियाकीय जरूरतों को पूरा करने के लिये मार्च को समाप्त चालू वित्त वर्ष के बचे दो महीनों में शेयर और बांड जारी कर करीब 10,000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बना रहे हैं। पिछले कुछ महीनों में भारतीय स्टेट बैंक, केनरा बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने बाजार से करीब 50,000 करोड़ रुपये जुटाये थे। वित्तीय सेवा सचिव देबाशीष पांडा ने पीटीआई-भाषा से कहा, ''बैंकों ने बाजार से 50,700 करोड़ रुपये जुटाये हैं तथा हम चालू वित्त वर्ष के बचे महीनों में 8,000 से 10,000 करोड़ रुपये और जुटाने की उम्मीद कर रहे हैं।'' कोविड-19 के कारण कर्ज वसूली में कठिनाइयों के विषय में उन्होंने कहा कि बैंकों ने कुछ मामलों में ऋण वापसी में समस्या को भांपते हुए पर्याप्त प्रावधान किये हैं। पांडा ने कहा कि सरकार ने 2021-22 के लिये 20,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया है। इसका उपयोग जरूरत पड़ने पर किया जाएगा।

ई-वे बिल डिफाल्ट पर देना होगा 200 फीसद जुर्माना, जीएसटी में भी हुए कई बदलाव

हल्द्वानी। एजेंसी

आम बजट से पहले जीएसटी में सुधार की मांग राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही थी। ऐसे में बजट जारी होने के बाद जीएसटी के लिहाज से कई अहम बदलाव देखने को मिल रहे हैं। जिससे ई-वे बिल डिफाल्ट के मामले में जुर्माना कड़ा करते हुए इसे 200 फीसद कर दिया गया है। जबकि जीएसटीआर-9सी को खत्म करने से रिटर्न फाइलर को राहत दी गई है। वस्तु व सेवा कर लागू होने के बाद से इसे कठिन पहेली के रूप में देखा जाता रहा है। जीएसटी की प्रक्रिया आसान बनाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। जिससे लोग आसानी से जीएसटी की प्रक्रिया को पूरी कर सकें। ऐसे में नए बजट में वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण ने जीएसटी को बहुत हद तक आसान बनाया है। जिसका लाभ लोगों को मिलना शुरू हो जाएगा। पहले ई-वे बिल में किसी तरह की गड़बड़ी पर टैक्स और उतना ही जुर्माना लगाया जा रहा था। अब टैक्स के बजाय दो गुनी राशि का जुर्माना लिया जाएगा। राज्य कर अधिकारी प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि अभी तक जीएसटी रिटर्न दाखिल करते समय 9सी फार्म आवश्यक था। जिसमें वार्षिक स्टेटमेंट देते समय किसी सीए से ऑडिट कराना आवश्यक था। जिसमें वित्त मंत्री ने जीएसटीआर 9सी को समाप्त कर दिया है। जिससे कारोबारी को आडिट के लिए सीए का चक्कर नहीं लगाना होगा। नए बजट में अब फर्जी तरीके से आइटीसी क्लेम करना भी मुश्किल हो जाएगा। जबकि पूर्व में कई ऐसे मामले पकड़ में आ रहे थे, जिसमें बिना कुछ कारोबार के ही फर्जी बिल बनाकर खरीद और बिक्री दर्शाई गई थी। जिसके जरिए हजारों करोड़ का आइटीसी क्लेम कर लिया गया था। नई व्यवस्था में फार्म दो ए पर आधारित खरीद की ही आइटीसी क्लेम की जा सकेगी। राज्य कर अधिकारी प्रकाश त्रिवेदी ने बताया कि जीएसटी में नए सुधार लोगों के लिए बेहतर साबित होंगे।

ई-कॉमर्स कर पर अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की रिपोर्ट से सहमत नहीं है भारतः वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने बुधवार को कहा कि भारत, अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) की इस रिपोर्ट से सहमत नहीं है कि विदेशी ई-कॉमर्स कंपनियों पर दो प्रतिशत का समानता

शुल्क अमेरिकी कंपनियों के खिलाफ भेदभाव है। पिछले महीने एक यूएसटीआर जांच में यह निष्कर्ष निकाला गया था कि भारत में ई-कॉमर्स पर दो प्रतिशत का डिजिटल सेवा कर अमेरिकी कंपनियों के साथ भेदभाव करता है और यह अंतरराष्ट्रीय कर सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। वधावन ने संवाददाताओं से कहा, ''हम इस निष्कर्ष से सहमत नहीं हैं।'' उनसे पूछा गया था कि क्या भारत ने यूएसटीआर की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, ''मूल बात यह है कि यदि किसी निश्चित क्षेत्राधिकार से आर्थिक लाभ होता है तो उस क्षेत्राधिकार में कुछ कराधान होना चाहिए... ओईसीडी (आर्थिक सहयोग और विकास संगठन) भी इस दिशा में आगे बढ़ रहा है कि यदि आर्थिक उपस्थिति और आर्थिक लाभ है, तो उस क्षेत्राधिकार में कराधान होना चाहिए। आपको एक निश्चित क्षेत्राधिकार में अरबों डॉलर की कमाई हो रही है, तो आपको करों का भुगतान करना होगा।'' उन्होंने कहा कि कुछ देश विरोध कर रहे हैं क्योंकि उनका उस तरह की गतिविधियों में बहुत बड़ा वर्चस्व है, चाहे वह फेसबुक हो, गूगल हो या अमेजन हो। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित लघु व्यापार सौदे पर प्रगति के बारे में उन्होंने कहा कि द्विपक्षीय चर्चा हमेशा जारी रहती है और वे कभी खत्म नहीं होती हैं।

BUDGET 2021

बजट से बदलेगा भारत के हेल्थकेयर का इन्फ्रास्ट्रक्चर, होंगे ये नए बदलाव

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

मोदी सरकार की बड़ी फिक्र हमेशा आम लोगों की सेहत रही है और बजट में हेल्थ का हिस्सा भी सरकार हर साल बढ़ाती रही है। लेकिन कोरोना काल ने सरकार की ये फिक्र और बढ़ा दी। इस दौरान 130 करोड़ लोगों के सेहत की सीधी जिम्मेदारी सरकार की थी। यही वजह है कि इस बार बजट में स्वास्थ्य सेक्टर को सबसे ऊपर रखा गया और हेल्थ बजट में 135 पर्सेंट की बढ़ोतरी की गई। एक्सपर्ट सरकार के इस फैसले की भी तारीफ कर रहे हैं। खासतौर से तब जब बजट पेश किए हुए 32 घंटे से ज्यादा बीत गए हैं इसे समझने की जरूरत भी बढ़ गई है।

भारत के अस्पतालों में ही डेढ़ लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस से काल के गाल में समा गए. हजारों हजार परिवार तबाह हो गए। वायरस का कहर देश के एक करोड़ से ज्यादा लोगों पर टूटा. पिछले एक साल में इस महामारी ने पूरे हेल्थ सेक्टर को सिर के बल खड़ा कर दिया। हर दिन देश की स्वास्थ्य व्यवस्था के सामने नई और बड़ी चुनौती आती रही। ये फिक्र बड़ी थी, क्योंकि ये आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा था। आत्मनिर्भर भारत की तरक्की से जुड़ा था। लिहाजा बजट में आम आदमी की जिंदगी का खास ख्याल रखा गया और आम बजट को हेल्थ बजट जैसा बनाया गया ताकि फिर से लोगों की सेहत परिवार और देश के विकास में बाधा ना बनें और अर्थव्यवस्था पटरी पर सरपट दौड़ती रहे। इसे ऐसे भी समझ सकते हैं। स्वास्थ्य बजट में 135 पर्सेंट का इजाफा हुआ. इसे 94 हजार से 2.38 लाख करोड़ किया गया है। साफ है कोरोना वायरस ने सेहत को लेकर पूरी सोच ही बदल दी है और आम हिंदुस्तानी की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर सरकार का नजरिया भी।

6 साल नें 64 हजार करोड़ का खर्च

इसीलिए आने वाले समय में किसी भी महामारी से निपटने के लिए बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाओं का नेटवर्क बढ़ाना ज्यादा जरूरी था। इसी मिशन के लिए सरकार 6 साल में 64,180 करोड़ रुपये खर्च करेगी, जिसे प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना के जरिए पूरा किया जाएगा। इस बजट में गांवों के प्राइमरी हेल्थ सेंटर को बहतर बनाने से लेकर 602 जिलों में क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल शुरू करने की योजना तक शामिल है।

लक्ष्य इतना आसान नहीं

जाहिर है बजट के जरिए सरकार ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में पुरजोर ध्यान दिया, जिसमें राष्ट्रीय स्तर के साथ ही प्राइमरी और सेकेंड्री हेल्थ केयर की सुविधा पर भी खर्च करने की योजना है। सरकार स्वास्थ्य सुविधाओं को गांव, छोटे शहर और जिले के स्तर पर मजबूत करना चाहती है। जहां देश की 70 से 80 फीसदी आबादी रहती है। इसके मायने बड़े हैं. बजट में आपकी जिंदगी को सेहतमंद और स्वस्थ्य बनाने का पूरा प्लान है। 130 करोड़ की आबादी वाले देश में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत मिशन को पूरा करना इतना आसान नहीं है। जिस देश में एक साल पहले तक मास्क, सेनिटाइजर और पीपीई किट तक विदेशों से आयात किए गए वहां आत्मनिर्भर होना एवरेस्ट की चढ़ाई से कम नहीं। लेकिन हिंदुस्तान ने जिस तरह से इन चुनौतियों का सामना किया और जीत हासिल की। ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान में हर मुश्किल को हराने की क्षमता है. अब इसे आगे बढ़ाने की जरुरत है। सरकार भी समझ गई कि अब देश में ही शोध संस्थानों के जरिए मेडिकल रिसर्च को मजबूत करना होगा। जांच और लैब की संख्या बढ़ानी होगी, जिसका सीधा सरोकार आम लोगों से होगा. वित्त मंत्री की घोषणा में देश में 75 हजार ग्रामीण हेल्थ सेंटर, सभी जिलों में जांच केंद्र, नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल और इंटिग्रेटेड हेल्थ इन्फो पोर्टल को मजबूत करने जैसी अहम

बातें हैं। इससे गांवों के 17 हजार रूरल हेल्थ सेंटर समेत शहरों के 11 हजार अर्बन हेल्थ और वेलनेस सेंटर को मजबूती मिलेगी। इसका मतलब ये है कि अब स्वास्थ को आम लोगों तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकताओं में अहम है और देश की सेहत का सीधा कनेक्शन देश की तरक्की से भी है, जिसमें बीमारियों पर खर्च कम होगा और बचत ज्यादा होगी. साथ ही स्वस्थ भारत और आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा होगा।

विनिवेश के जरिए पैसा जुटाना

बजट में सरकार का फोकस आम लोगों की सेहत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर है। भले ही सीधे तौर पर आपकी जेब में चंद पैसे नहीं डाले गए हैं लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और हेल्थ सेक्टर को मजबूत कर इकॉनमी को बूस्टर डोज जरूर दिया गया है। लेकिन अब सवाल है कि इस मिशन को पूरा करने के लिए पैसे कहां से आएंगे। देश की जीडीपी को बढ़ाने के लिए निवेश कहां से आएगा. सरकार ने इस काम के लिए रिफॉर्म का रास्ता चुना है। सरकार का लक्ष्य विनिवेश के जरिए पौने दो लाख करोड़ रुपये जुटाने का है। मतलब ये कि सरकार विनिवेश के जरिए ही आर्थिक सुधार की जमीन मजबूत करेगी और पैसे का इंतजाम करेगी. अब एक बार फिर सवाल उठता है कि आखिरकार सरकार ये कैसे करेगी. वित्त मंत्री ने रकम जुटाने को लेकर अपनी योजना भी बताई है, तो पहले इसे समझिए।

आने वाले समय में सरकार दो सरकारी बैंकों और एक जनरल बीमा कंपनी का निजीकरण करेगी. इसके साथ ही ध्ध्य की हिस्सेदारी को बेचने का लक्ष्य भी पूरा किया जाएगा। सरकार भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया, कंटेनर कॉर्पोरेशन, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ़ इंडिया, नीलांचल इस्पात निगम लिमिटेड, बीईएमएल, पवन हंस और एयर इंडिया समेत कई दूसरी कंपनियों की हिस्सेदारी बेचकर रकम जुटाई जाएगी। सरकार के रिफॉर्म की तारीफ हर बिजनेस फोरम पर हो रही है। जानकार इसे साहसी और दूरदर्शी फैसला बता रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी और भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने में मददगार होगा।

सऊदी अरब ने 20 देशों को दिया झटका, विदेशियों के यात्रा करने पर लगाई रोक

रियाद। एजेंसी

सऊदी अरब ने भारत-पाकिस्तान समेत 20 देशों को बड़ा झटका दिया है। सऊदी अरब की सरकार ने मंगलवार को इन देशों से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया। सऊदी अरब ने कोरोना वायरस पर काबू पाने के लिए यह प्रतिबंध लगाया है। हालांकि इस यात्रा प्रतिबंध में राजनयिकों, सऊदी नागरिकों, डॉक्टरों और उनके परिवार को छूट दी गई है। सऊदी अरब के इस प्रतिबंध से कई भारतीय प्रभावित हो सकते हैं जो सऊदी अरब में काम करते हैं। सऊदी सरकार ने कहा कि यह प्रतिबंध अल्पकालिक है और बुधवार रात 9 बजे से यह यात्रा प्रतिबंध लागू होगा। यह प्रतिबंध पड़ोसी मिस्र, यूएई, लेबनान, जर्मनी, ब्रिटेन, आयरलैंड, इटली, अमेरिका आदि शामिल हैं। इस यात्रा प्रतिबंध में कहा कि सऊदी अरब सरकार यह सुनिश्चित करने का प्रयास करेगी कि इन देशों के साथ सप्लाइ चेन बनी रहे और जहाजों का आना-जाना जारी रहे।

सऊदी ने पाकिस्तान से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगाया

सऊदी सरकार ने कहा कि देश के नागरिकों, राजनयिकों और स्वास्थ्यकर्मियों तथा उनके परिवार को इन देशों से आने की अनुमति होगी लेकिन उन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय के बचाव के नियमों का पालन करना होगा। उधर, पाकिस्तान इंटरनैशनल एयरलाइंस ने बताया कि सऊदी अधिकारियों ने मंगलवार रात से पाकिस्तान से लोगों के आने पर प्रतिबंध लगा दिया है। सऊदी अरब ने यह यात्रा प्रतिबंध ऐसे समय पर लगाए हैं जब सऊदी अरब के स्वास्थ्य मंत्री तौफिक अल-रबियाह ने रविवार को चेतावनी दी कि अगर लोगों ने स्वास्थ्य प्रतिबंधों का पालन नहीं किया तो नए कोरोना वायरस प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं। बता दें कि भारत और पाकिस्तान से लाखों की तादाद में लोग सऊदी अरब में काम करते हैं। इस ताजा प्रतिबंध का असर उन पर पड़ सकता है।

सावधान! ब्रिटेन में मिले कोरोना वायरस के नए स्वरूप में फिर से आ सकता है घातक बदलाव

लंदन। एजेंसी

ब्रिटेन के वैज्ञानिकों ने आगाह किया है कि पिछले साल दक्षिणी इंग्लैंड में सामने आए कोरोना वायरस के अत्यंत संक्रामक और ज्यादा घातक स्वरूप में बदलाव के संकेत दिख रहे हैं। परीक्षण के दौरान इंग्लैंड के कैंट क्षेत्र में मिले वायरस के स्वरूप में बदलाव का पता चला है और इसे 'ई484 के' नाम दिया गया है। इससे पहले दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में कोरोना वायरस के स्वरूपों में भी बदलाव का पता चला था।

मौजूदा टीके इससे बचाव करने में कम प्रभावी रहेंगे

ऐसी आशंका है कि वायरस के स्वरूप में आया यह बदलाव प्रतिरक्षा तंत्र को भेद सकता है और मौजूदा टीके इससे बचाव करने में कम प्रभावी रहेंगे। कैंब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ थेरेपेटिक इम्यूनोलॉजी एंड इन्फेक्शन्स डिजीज (सीआईटीआईआईडी), यूनिवर्सिटी ऑफ कैंब्रिज में हुए शोध की विश्लेषकों ने अभी समीक्षा नहीं की है. शोधकर्ताओं ने 'नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ रिसर्च' के साथ तालमेल से यह शोध किया है।

स्वरूप में बदलाव आना चिंता की बात- शोधकर्ता

सीआईटीआईआईडी में अग्रणी शोधकर्ता रवि गुप्ता ने कहा, "सबसे ज्यादा चिंता वायरस के स्वरूप ई484 को लेकर है, जिसका संक्रमण अब तक कुछ ही लोगों में मिला है। हमारे शोध में संकेत मिला है कि इस स्वरूप पर टीका कम प्रभावी होगा।" उन्होंने कहा कि वायरस के इस स्वरूप में भी बदलाव आता दिख रहा है जो कि चिंता की बात है। उन्होंने कहा, "हमें वायरस के नए स्वरूप को देखते हुए अगली पीढी के टीके के हिसाब से तैयारी करनी होगी। हमें संक्रमण रोकने के लिए टीका निर्माण के काम में और तेजी लाने की जरूरत है।" शोध के मुख्य निरीक्षणकर्ता डॉ डमी कोलियर ने कहा, "हमारे आंकड़ों से पता चलता है कि 80 से ज्यादा उम्र के लोगों में टीके की पहली खुराक के तीन हफ्ते बाद सुरक्षात्मक एंटीबॉडी नहीं मिली। लेकिन, आश्वस्त करने वाली बात यह रही कि दो खुराकें लेने के बाद वायरस से मुकाबले के लिए प्रतिरक्षा तैयार हो गयी।"

विवाद समाधान समिति की कई शाखाएं होंगीः सीबीडीटी प्रमुख

नयी दिल्ली। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष पी सी मोदी ने बुधवार को कहा कि आम बजट में प्रस्तावित विवाद समाधान समित की कई शाखाएं होंगी, जिससे छोटे करदाताओं को अपीलीय प्रक्रिया से गुजरे बिना कर मामलों को निपटाने का मौका मिलेगा। मोदी ने कहा कि आयकर विभाग करदाताओं को सही कर रिटर्न दाखिल करने में मदद के लिए भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) या कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (एमसीए) से 26एएस के रूप में मिलने वाली सभी सूचनाएं उपलब्ध कराएगा। उन्होंने बजट के बाद एसोचैम के एक कार्यक्रम में कहा, "हम लगातार यह सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं कि करदाता स्वेच्छा से कर कानूनों का पालन करें और ईमानदार करदाताओं को ऐसी सभी सुविधाएं मिलें, जिसके वे हकदार हैं और इसके साथ ही जो लोग गलत तरीके से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, उनका भी ध्यान रखा जाएगा।" वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने 2021-22 के बजट भाषण में कहा था कि छोटे करदाताओं के मुकदमेबाजी को कम करने के लिए विवाद समाधान समिति (डीआरसी) की स्थापना की जाएगी, जहां 50 लाख रुपये तक कर योग्य आय और 10 लाख रुपये तक विवादित आय वाले करदाता अपील कर सकते हैं। मोदी ने कहा कि डीआरसी की स्थापना के पीछे सोच यह है कि निपटान आयोग वास्तव में छोटे करदाताओं की जरूरतों को पूरा नहीं करता था।

सेना के आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे: राजनाथ

बेंगलुरु। एजेंसी

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीन के साथ जारी सैन्य गतिरोध के बीच बुधवार को कहा कि भारत अपनी सीमाओं पर यथास्थिति में बदलाव की कोशिशों को लेकर सतर्क है और क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए किसी भी दुस्साहस से निपटने को तैयार है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सेना के आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च किए जाएंगे। सिंह ने यहां येलाहंका वायुसेना स्टेशन में आयोजित 'एरो इंडिया-2021' के उद्घाटन समारोह में कहा, ''हम अपनी अनसुलझी सीमाओं पर यथास्थिति बदलने के लिए बल की तैनाती के कई दुर्भाग्यपूर्ण प्रयासों को लंबे समय से देख रहे हैं।'' मंत्री ने कहा, ''भारत अपने लोगों एवं क्षेत्रीय अखंडता की हर कीमत पर रक्षा करने के लिए किसी भी दुस्साहस का सामना करने और उसे शिकस्त देने के लिए सतर्क एवं तैयार है।'' भारत और चीन के बीच पिछले साल पांच मई से पूर्वी लद्दाख में सैन्य गतिरोध बना हुआ है। दोनों देशों ने इस गतिरोध को सुलझाने के लिए कई दौर की वार्ता की है, लेकिन इसमें कोई विशेष प्रगति नहीं हुई है। तीन दिन तक चलने वाला एरो इंडिया शो एशिया की सबसे बड़ी रक्षा एवं वैमानिकी प्रदर्शनी है जिसका आयोजन 'आत्मनिर्भर भारत' और 'मेक इन इंडिया' की शक्ति के साथ कोविड-19 महामारी के बीच हो रहा है। इस तेरहवें द्विवार्षिक अंतरराष्ट्रीय आयोजन को विश्व का पहला हाइब्रिड एरोस्पेस शो कहा जा रहा है जिसका आयोजन भौतिक एवं डिजिटल दोनों तरह से हो रहा है। सिंह ने कहा कि भारत की योजना बड़े एवं जटिल मंचों के घरेलू विनिर्माण पर ध्यान केंद्रित करते हुए आगामी सात से आठ साल में रक्षा क्षेत्र के आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च करने की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने निर्यात एवं विदेशी प्रत्यक्ष निवेश के अनुकूल पारिस्थितिकी तंत्र बनाकर रक्षा क्षेत्र में 2014 के बाद से कई सुधार किए हैं। सिंह ने कहा कि आत्म-निर्भरता एवं निर्यात के दोहरे लक्ष्यों को हासिल करने के लिए, सरकार ने 2024 तक एरोस्पेस एवं रक्षा सामग्री और सेवाओं में 35,000 करोड़ रुपये के निर्यात समेत रक्षा विनिर्माण के क्षेत्र में 1,75,000 करोड़ रुपये की कुल बिक्री हासिल करने का लक्ष्य रखा है। उन्होंने कहा, ''हमारी आगामी सात से आठ साल में रक्षा आधुनिकीकरण पर 130 अरब डॉलर खर्च करने की योजना की।'' रक्षा मंत्री ने कहा कि अपने कई मित्रवत देशों की तरह भारत के सामने भी कई मोर्चों से खतरे और चुनौतियां पैदा हो रही हैं। उन्होंने कहा कि देश राज्य प्रयोजित आतंकवाद का पीड़ित रहा है और यह आतंकवाद अब एक वैश्विक खतरा बन गया है। सिंह ने कहा कि सरकार ने देश के रक्षा तंत्र को मजबूत बनाने के लिए हाल में कई कदम उठाए हैं। मंत्री ने कहा कि 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत बड़े एवं जटिल रक्षा मंचों का घरेलू विनिर्माण देश की नीति का केंद्र बन गया है। सिंह ने कहा कि उन्हें सूचित किया गया है कि इस समारोह में 55 से अधिक देशों की 80 विदेशी कंपनियों, रक्षा मंत्रियों, प्रतिनिधिमंडलों, सेवा प्रमुखों एवं अधिकारियों समेत करीब 540 प्रदर्शक हिस्सा ले रहे हैं। उन्होंने कहा, ''यह वैश्विक समुदाय में बढ़ते आशावाद को दर्शाता है।'' सिंह ने प्रदर्शनी में भौतिक रूप से शामिल हुए मालदीव, यूक्रेन, इक्वेटोरियल गिनी, ईरान, कोमोरोस और मैडगास्कर के रक्षा मंत्रियों का आभार व्यक्त किया तथा उन देशों के रक्षा मंत्रियों का भी आभार व्यक्त किया जो इस कार्यक्रम में डिजिटल रूप से शामिल हो रहे हैं। सिंह ने वैश्विक कंपनियों को सरकार की विभिन्न पहलों का लाभ उठाकर भारत में अपनी उत्पादन इकाइयां स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया। उन्होंने कहा कि इस साल के कार्यक्रम में वैश्विक महामारी से उत्पन्न चुनौतियों के बावजूद इतनी बड़ी संख्या में प्रतिभागियों के आने से वह बेहद खुश हैं। एरो इंडिया शो में हिन्द महासागर क्षेत्र में शांति, सुरक्षा एवं सहयोग विषय पर हिन्द महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों का सम्मेलन भी हो रहा है।

Aero India 2021

बेंगलुरु एयर शो में दुनिया देख रही भारत की ताकत का 'तेज'

बेंगलुरु। एजेंसी

बेंगलुरु में 13 वें एयरो इंडिया-2021 शो का आयोजन शुरू हो गया है। इस बार का एयर शो काफी खास है। तेजस से लेकर कई स्वदेशी एयरक्राफ्ट इस बार एयरशो में करतब दिखा रहे हैं। इस बार के एयरो इंडिया में दुनियाभर के कई देश भारत की ताकत को देख रहे हैं। एयर शो के पहले दिन HAL के साथ एयरफोर्स का 83 तेजस जेट लेने के लिए करार भी हुआ। इसके अलावा सारंग एयरोबेटिक्स हलिकॉप्टर टीम और सूर्यकिरण टीम ने पहली बार एक साथ दम दिखाया। इस मौके पर रक्षामंत्री राजनाथ सिंह और रक्षा प्रमुख बिपिन रावत मौजूद रहे। कोरोना के चलते इस बार शो को छोटा करके तीन दिन का कर दिया गया है। यह एयर शो 5 फरवरी को खत्म होगा।

अमेरिका से उड़कर 26 घंटे में भारत पहुंचा B-1 B लांसर

अमेरिकी बी-1बी लांसर एयरक्राफ्ट ने भी कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस विमान को संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण डकोटा के एक एयरबेस से उड़ान भरकर बेंगलुरू तक आने में 26 घंटे का समय लगा।

सूर्यकिरण और सारंग ने साथ में दिखाया दम

बेंगलुरु में हो रहा एयरो इंडिया शो कई मायनों में खास है। इससे पहले विदेश से लोग अपनी टेक्नॉलजी यहां लाकर शोकेस करते थे, और यहां की इंडस्ट्री उनके साथ हाथ मिलाकर उस टेक्नॉलजी को हासिल करती थी। अब भारत शोकेस कर रहे हैं। इस बार शो में एचएएल द्वारा निर्मित लाइट कॉम्बैट हेलिकॉप्टर करतब दिखा रहे हैं। इन हेलिकॉप्टरों में में जहां से धुआं निकलता है उसे स्टफ विंग्स कहते हैं। जिनमें हार्ड पॉइंट्स होते हैं जिनमें हथियार लोड किए जाते हैं। रॉकेट या मिसाइल यहां पर लोड होती है।

400 किमी दूरी तक निशाना साधेगी मिसाइल

एयर शो में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल के एयर लॉन्च्ड वर्जन से इक्विप्ड सु-30 एमकेआई फाइटर जेट भी प्रदर्शित किया गया। वायु सेना का एक समर्पित स्क्वाड्रन इन मिसाइलों से लैस है जो 400 किमी से अधिक दूरी पर निशाना साध सकती है।

सारंग और सूर्यकिरण टीम ने एक साथ दिखाया करतब

एयरो इंडिया में सारंग एयरोबेटिक हेलिकॉप्टर टीम और सूर्यकिरण टीम एक साथ डिस्प्ले कर रही है। अभी तक दोनों टीम अलग-अलग एयरोबेटिक करती थीं लेकिन इस बार हेलिकॉप्टर और फिक्स्ड विंग की डिस्प्ले फ्लाइट एक साथ प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी हेलिकॉप्टर भारत के ही हैं। अडवांस लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव को एयरोबेटिक टीम में कन्वर्ट किया गया है। इस दौरान पायलट ने कौशल क्षमता और एकाग्रता का प्रदर्शन किया।

एयर शो में दिखा आत्मनिर्भर भारत

एयरो इंडिया में इस बार तकनीक के मामले में भारत की ताकत दिखाई जा रही है। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भारत किस तरह बढ़ रहा है इसकी झलक देखने को मिली। इस बार सेंट्रल थीम एचएएल (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) की रोटरी विंग है। एचएएल के अडवांस लाइट हेलिकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर, मिडियम कॉम्बेट हेलिकॉप्टर के मॉडल भी डिस्प्ले किए गए।

55 से अधिक देशों ने लिया हिस्सा

एयरो इंडिया में 55 से अधिक देशों के अधिकारी, सर्विस चीफ, प्रतिनिधि, रक्षा मंत्री और 80 विदेशी कंपनी समेत 540 एग्जिबिटर्स ने भाग लिया। वहीं एचएल के साथ 83 नए स्वदेशी लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट का कॉन्ट्रैक्ट भी हुआ।

तेजस के साथ दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट ने भी भरी उड़ान

एचएएल की 'आत्मनिर्भर फॉर्मेशन फ्लाइट' में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस के साथ फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। इसमें एचएएल के बनाए हुए एलसीए ट्रेनर, एचटीटी-40, आईजेटी, अडवांस्ड हॉक एमके -132 और सिविल डोर्नियर-228 एयरक्राफ्ट ने उड़ान भरी। इसके अलावा सुखोई-30 एमकेआई, एडवांस्ड लाइट हेलिकॉप्टर ध्रुव, लाइट कॉम्बेट हेलिकॉप्टर, लाइट यूटिलिटी हेलिकॉप्टर ने भी एयरशो में दम दिखाया।

भारतीय नौ सेना में शामिल होगी ब्रह्मोस मिसाइल

एयरो इंडिया शो में ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का भी प्रदर्शन हुआ। भारतीय नौसेना के खेमे में यह मिसाइल नेक्स्ट जेनरेशन मैरिटाइम मरीन कोस्टल डिफेंस बैटरी रोल का हिस्सा बनने जा रही है।

रैम्पेज एयर-टु-ग्राउंड मिसाइल वायुसेना में होगी शामिल

इजराइल के एलबिट सिस्टम ने बेंगलुरु के एयरो इंडिया शो में अपनी रैम्पेज एयर-टू-ग्राउंड मिसाइल का प्रदर्शन किया। इस मिसाइल को भारतीय वायु सेना में शामिल किया जा रहा है।

5 फरवरी तक चलेगा एयर शो

3 फरवरी से शुरू होकर यह एयरो इंडिया शो 5 फरवरी तक चलेगा। रक्षा मंत्रालय का यह एयरो इंडिया शो दो साल में एक बार होता है। यह एशिया का सबसे बड़ा एयर शो है। जिसमें एविएशन सेक्टर के मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से लेकर भारत की एयरफोर्स से लेकर दुनिया के कई देशों की एयरफोर्स के प्रतिनिधि भी रहते हैं।

कोविड के चलते आम दर्शकों को एंट्री नहीं

दुनिया में डिफेंस एविशएन में क्या नई तकनीक आई है इसका पता चलता है साथ ही एयरफोर्स की जरूरत के मुताबिक अगर कोई नई तकनीक या साजो सामान का पता चलता है तो यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां उससे जुड़ी पूरी जानकारी मिल जाती है। कोविड-19 की वजह से इस बार आम लोगों की एयरो इंडिया में एंट्री नहीं होगी लेकिन वह वर्चुअली एयरो इंडिया शो देख सकते हैं।

षट्तिला एकादशी कब है?

जानें तारीख, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि

हिंदू धर्म कई व्रत और त्योहारों का अनोखा संगम है. हर व्रत और त्योहार का अपना अलग महत्व, पूजा विधि और मान्यताएं होते हैं. एकादशी व्रत की हिंदू धर्म में बहुत मान्यता है. षट्तिला एकादशी भी एक ऐसा ही व्रत है. षट्तिला एकादशी व्रत इस बार 7 फरवरी 2021 (रविवार) को पड़ रहा है. यह व्रत भगवान कृष्ण और लक्ष्मीपति विष्णु भगवान को समर्पित माना जाता है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, जो जातक सच्चे मन से इस व्रत का विधि-विधान से पालन करता है उसे जीवन में सभी प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है. आइए जानते हैं षट्तिला एकादशी का शुभ मुहूर्त, और पूजा विधि...

षट्तिला एकादशी शुभ मुहूर्त :

एकादशी तिथि का प्रारंभः 7 फरवरी 2021 सुबह 06 बजकर 26 मिनट से व्रत शुरू हो जाएगा.

एकादशी तिथि समाप्तः 8 फरवरी 2021 सुबह 04 बजकर 47 मिनट तक व्रत का पारण कर लें.

षट्तिला एकादशी व्रत पूजा विधिः

■षट्तिला एकादशी का व्रत करने वाले जातक को सुबह जल्दी उठना चाहिए और नित्यकर्म और स्नान करके पूजा स्थल की साफ-सफाई करनी चाहिए.

■पूजा की चौकी साफ करके इसपर पीला या लाल कपड़ा बिछाएं. अब इसपर कृष्ण और विष्णु भगवान की मूर्ति या तस्वीर स्थापित करें.

■ पूजा करते समय भगवान कृष्ण के भजन और विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और प्रसाद, तुलसी जल, फल, नारियल, अगरबत्ती और फूल देवताओं को अर्पित करें.

■व्रत के अगले दिन यानी कि द्वादशी पर पूजा के बाद भोजन का सेवन करने के बाद षट्तिला एकादशी व्रत का पारण करें.

■ पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, षट्तिला एकादशी के दिन तिल को पानी में डालकर नहाना मंगल फलदायक माना जाता है. इसके साथ ही भगवान विष्णु को भी पूजा के दौरान तिल अर्पित करने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है. यह भी माना जाता है कि इस दिन गरीब या जरूरतमंद को तिल का दान देना शुभ होता है. कई लोग इस एकादशी में तिल से बनी सेवइयां भी खाते हैं.

बच्चों को काला टीका लगाने का वैज्ञानिक कारण

अक्सर देखा जाता है कि छोटे बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। टीका लगाने के बारे में जानकारों का कहना है कि टीका बच्चों को बुरी नजर से बचाने के लिए लगाया जाता है। अक्सर देखा जाता है कि पूजा-पाठ में कभी भी काले रंग के कपड़ों या किसी तरह की काली वस्तु का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। क्योंकि काले रंग को नकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक माना जाता है। बच्चे पर किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जा अर्थात किसी तरह की बुरी नजर न लगे, इसलिए काला टीका या काला धागा बंधा जाता है। बच्चों का काला टीका लगाने के कुछ वैज्ञानिक कारण भी बताए जाते हैं। कहा जाता है कि काली वस्तु हर प्रकार का विकिरण अवशोषित करने की क्षमता रखती है। काला टीका लगाने की वजह से बच्चों के शरीर पर पड़ने वाले विकिरण के प्रभाव की संभावना खत्म हो जाती है। यही वजह है कि बच्चों को काला टीका लगाया जाता है। वहीं काला रंग बच्चे को देखने वाली की एकाग्रता को भी भंग कर देता है।

ग्रह परिवर्तन : 4 फरवरी से बन रहा है पंचग्रही योग, क्या होगा 12 राशियों पर असर

मकर राशि में चार ग्रह सूर्य, बृहस्पति, शनि और शुक्र चल रहे हैं। 4 फरवरी को इसी राशि में बुध के प्रवेश करने से पंचग्रही योग बनेगा। यह योग 12 फरवरी तक चलेगा। 12 फरवरी को सूर्य के कुंभ राशि में जाने के कारण यह पंचग्रही ये चतुर्ग्रही योग हो जाएगा। इसके बाद 20 फरवरी को शुक्र के कुंभ राशि में जाने से चतुर्ग्रही योग भी समाप्त हो जाएगा। पंचग्रही और चतुर्ग्रही योग का विपरीत प्रभाव उन लोगों पर ज्यादा रहेगा जिन्हें शनि की साढ़ेसाती चल रही है या जिनकी कुंडली में सूर्य पीड़ाकारी ग्रह के रूप में स्थित है। पंचग्रही योग के दौरान आय प्रभावित होगी। कार्यों की गति मंद होगी, व्यर्थ के वाद-विवाद और खर्च में बढ़ोतरी होगी।

मेष : दांपत्य जीवन में मिठास, कानूनी मामलों में विजय, व्यापार में लाभ, पैसों की आवक।

वृषभ : भौतिक सुख वृद्धि, कारोबार वृद्धि, धनागम, स्वास्थ्य सुख।

मिथुन : मेहनत अधिक करना होगी। कार्य को गति देने का प्रयास करें। धन वृद्धि होगी।

कर्क : भाग्य का साथ मिलेगा। आय बढ़ेगी। स्वास्थ्य सुधार होगा। लाभ होगा।

सिंह : स्वास्थ्य का ध्यान रखें। निवेश से लाभ होगा।

कन्या : वैवाहिक, साझेदारी के कार्यों में सतर्क रहें। निर्णय क्षमता प्रभावित होगी। निवेश से बचें।

तुला : समस्याएं कम होंगी। आय बढ़ेगी। स्वास्थ्य ठीक रहेगा। बड़ा निर्णय लेंगे।

वृश्चिक : सुख-सम्मान में वृद्धि, शिक्षा में लाभ, धन आगमन, बौद्धिक कार्य से लाभ।

धनु : पैतृक संपत्ति प्राप्ति, धन लाभ, संतान सुख, प्रेम प्राप्ति।

मकर : धन लाभ, नवीन कार्य की प्राप्ति, भौतिक संसाधन की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ।

कुंभ : वाणी में मधुरता, यश और सम्मान की प्राप्ति, स्थान परिवर्तन।

मीन : आय में वृद्धि, संतान सुख, नया कारोबार, तरक्की, स्वास्थ्य लाभ।

सोमवार को भोलेनाथ की पूजा करते समय ध्यान रखें ये बातें, नहीं तो भगवान हो सकते हैं रुष्ठ

सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित है. ऐसे में कहा जाता है कि अगर सोमवार को भगवान शिव की सच्चे मन से पूजा की जाए तो सारे कष्टों से मुक्ति मिलती है और सभी मनोकामना पूरी होती है. शिव सदा अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं. मान्यता है कि भगवान शिव को खुश करने के लिए सोमवार को सुबह उठकर स्नान करके भगवान शिव की आराधना करनी चाहिए. इस दिन भगवान शंकर के साथ माता पार्वती और नंदी को गंगाजल चढ़ाना चाहिए. साथ ही इस दिन शिवजी पर खास तौर से चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, धतूरा या आंकड़े के फूल चढ़ाने चाहिए. ये सभी चीजें भगवान शिव की प्रिय हैं. इन्हें चढ़ाने पर भोलेनाथ खुश होकर अपनी कृपा बरसाते हैं. सोमवार के दिन भगवान शिव को घी, शक्कर और गेंहू के आटे से बने प्रसाद का भोग लगाना चाहिए. इसके बाद धूप, दीप से आरती करनी चाहिए. इसके बाद प्रसाद को गुरुजनों, बुजुर्गों और परिवार, मित्र सहित ग्रहण करें. मान्यता है कि सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप 108 बार करने से भगवान शिव

की विशेष कृपा प्राप्त होती है. सोमवार के दिन शिवलिंग पर गाय का कच्चा दूध चढ़ाने से भगवान शिव की कृपा हमेशा बनी रहती है. इसके अलावा भगवान के अन्य मंत्रों का भी स्मरण करने से भगवान की कृपा बरसती है.

भगवान शिव का मंत्र-

नमः शिवाय, ऊँ नमः शिवाय?

शिव पूजा में इन बातों का रखें खास ख्याल

शिव पूजा में बहुत सी ऐसी चीजें अर्पित की जाती हैं जो अन्य किसी देवता को नहीं चढ़ाई जाती, जैसे- आक, बिल्वपत्र, भांग आदि. इसी तरह माना जाता है कि शिव पूजा में कई ऐसी चीजें होती हैं जो आपकी पूजा का फल देने की बजाय आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं.

हल्दी

भगवान शिव की पूजा में हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है. हल्दी का इस्तेमाल मुख्य रूप से सौंदर्य प्रसाधन में किया जाता है. शास्त्रों के अनुसार शिवलिंग पुरुषत्व का प्रतीक है, इसी वजह से महादेव को हल्दी नहीं चढ़ाई जाती है.

फूल

शिव को कनेर और कमल के अलावा लाल रंग के फूल प्रिय नहीं हैं, शिव को केतकी और केवड़े के फूल चढ़ाने का निषेध किया गया है.

कुमकुम या रोली

शास्त्रों के अनुसार शिव जी को कुमकुम और रोली नहीं लगाई जाती है।

शिव पूजा में वर्जित है शंख

शंख भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय हैं, लेकिन शिव जी ने शंखचूर नामक असुर का वध किया था इसलिए शंख भगवान शिव की पूजा में वर्जित माना गया है.

नारियल पानी

नारियल पानी से भगवान शिव का अभिषेक नहीं करना चाहिए. मान्यता के अनुसार नारियल को लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, इसलिए सभी शुभ कार्य में नारियल को प्रसाद के तौर पर ग्रहण किया जाता है लेकिन कहा जाता है कि शिव पर अर्पित होने के बाद नारियल पानी ग्रहण योग्य नहीं रह जाता है.

तुलसी

तुलसी का पत्ता भी भगवान शिव को नहीं चढ़ाना चाहिए. इस संदर्भ में असुर राज जलंधर की कथा है जिसकी पत्नी वृंदा तुलसी का पौधा बन गई थी. भगवान शिव ने जलंधर का वध किया था इसलिए वृंदा ने भगवान शिव की पूजा में तुलसी के पत्तों का प्रयोग न करने की बात कही थी.

सूर्यदेव के नामों के पीछे छिपी हैं ये पौराणिक कथाएं

रविवार के दिन सूर्य देव की पूजा का विधान है. पौराणिक मान्यताओं के अनुसार, सूर्य देव प्रत्यक्ष रूप से दर्शन देने वाले देवता हैं. पौराणिक वेदों में सूर्य का उल्लेख विश्व की आत्मा और ईश्वर के नेत्र के तौर पर किया गया है. सूर्य की पूजा से जीवनशक्ति, मानसिक शांति, ऊर्जा और जीवन में सफलता की प्राप्ति होती है. सूर्यदेव को उगते और डूबते दोनों तरह से अर्घ्य दिया जाता है. शास्त्रों में सबसे ऊपर सूर्य देवता का स्थान रखा गया है. अगर सूर्य देव की पूजा की जाए तो कहा जाता है कि व्यक्ति के हर तरह के कष्ट दूर हो जाते हैं. सूर्य देव के कई नाम हैं. इन्हें आदित्य, भास्कर जैसे कई नामों से जाना जाता है. इन सभी नामों का महत्व अलग है. सभी के पीछे एक पौराणिक कथा छिपी है. आइए आपको बताते हैं इसके बारे में.

आदित्य और मार्तण्ड : देवमाता अदिति ने असुरों के अत्याचारों से परेशान होकर सूर्यदेव की तपस्या की थी. साथ ही उनसे उनके गर्भ से जन्म लेने की विनती की थी. उनकी तपस्या के प्रसन्न होकर सूर्यदेव ने अदिति के गर्भ से जन्म लिया और इसी के चलते वो आदित्य कहलाए. कुछ कथाओं के अनुसार, अदिति ने सूर्यदेव के वरदान से हिरण्यमय अंड को जन्म दिया था. तेज के कारण यह मार्तण्ड कहलाए.

दिनकरः सूर्यदेव दिन पर राज करते हैं. इसी के चलते इन्हें दिनकर भी कहा जाता है. दिन की शुरुआत और अंत सूर्य से ही होता है. इसी के चलते इन्हें सूर्य देव भी कहा जाता है.

भुवनेश्वर : इसका अर्थ पृथ्वी पर राज करने वाला होता है. सूर्य से ही पृथ्वी का अस्तित्व है. अगर सूर्यदेव न हो तो धरती का कोई अस्तित्व नहीं होगा. इसके चलते इन्हें भुवनेश्वर कहा जाता है.

सूर्यः शास्त्रों में सूर्य का अर्थ चलाचल बताया गया है. इसका मतलब होता है जो हर वक्त चलता हो. भगवान सूर्य संसार में भ्रमण कर सभी पर अपनी कृपा बरसाते हैं जिसके चलते इन्हें सूर्य कहा जाता है.

आदिदेव : ब्रह्मांड की शुरुआत सूर्य से और अंत भी सूर्य में ही समाहित है. इसलिए इन्हें आदिदेव भी कहा जाता है.

रविः मान्यता है कि जिस दिन ब्रह्मांड की शुरुआत हुई थी उस दिन रविवार था. ऐसे में इस दिन के नाम पर सूर्यदेव का नाम रवि पड़ गया

Vehicle Scrappage Policy in Budget 2021:

नई व्हीकल पॉलिसी आने के बाद पुरानी कार चलाना पड़ेगा महंगा

नई दिल्ली। एजेंसी

जब अगले वित्त वर्ष से नई व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी लागू हो जाएगी तो फिर 15 साल से पुरानी गाड़ियां रखना बहुत ही महंगा पड़ेगा। इसकी वजह ये है कि फिटनेस सर्टिफिकेट लेने की कीमत 62 गुना से भी अधिक हो जाएगी और प्राइवेट व्हीकल के रजिस्ट्रेशन को रीन्यू कराने की लागत भी करीब 8 गुना अधिक हो जाएगी। इतना ही नहीं, हर राज्य रोड टैक्स के अलावा ग्रान टैक्स भी लगाएंगे, जिसे गाड़ी के मालिक को चुकाना ही होगा। सड़क यातायात मंत्रालय की तरफ से अगले दो हफ्तों में स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार 15 साल से पुरानी कमर्शियल गाड़ियों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट फीस मौजूदा की 200 रुपये से बढ़कर 7500 रुपये कैब के लिए हो जाएगी और ट्रक के लिए 12,500 रुपये हो जाएगी।

हर साल 62 गुना बढ़ी फिटनेस सर्टिफिकेट फीस, ऊपर से ग्रीन टैक्स

मोटर व्हीकल कानून के अनुसार अगर गाड़ी 8 साल से पुरानी हो जाती है तो हर साल उसका फिटनेस सर्टिफिकेट रीन्यू कराना होगा। सूत्रों के अनुसार जब ये गाड़ियां 15 साल से पुरानी हो जाएंगी तो हर साल 62 गुना अधिक हो चुका फिटनेस सर्टिफिकेट पानी की फीस चुकाने से बेहतर लोगों को ये लगेगा की वह गाड़ी को स्क्रैप में ही दे दें, जो लोगों को पुरानी गाड़ी रखने के लिए हतोत्साहित करेगा। इन सबके अलावा राज्यों की तरफ से रोड टैक्स का करीब 10-25 फीसदी तक ग्रीन टैक्स भी लगाया जाएगा।

5000 रुपये तक बढ़ जाएगी कार की रजिस्ट्रेशन फीस

वहीं 15 साल से पुरानी प्राइवेट गाड़ियों के लिए भी चार्जेज बढ़ जाएंगे। दोपहिया वाहन का रजिस्ट्रेशन चार्ज मौजूद के 300 रुपये से 1000 रुपये हो जाएगा और कारों के लिए ये चार्ज 600 रुपये से बढ़कर 5000 रुपये हो जाएगा। राज्यों की तरफ से रोड टैक्स के अलावा गाड़ी पर करीब 5 साल के लिए ग्रीन टैक्स भी लगा दिया जाएगा। हर प्राइवेट गाड़ी का 15 साल के बाद रजिस्ट्रेशन रीन्यू कराना होगा और उसके बाद यही प्रक्रिया हर 5 साल के बाद होगी।

लेकिन सरकार के सामने हैं कई चुनौतियां

जो भी गाड़ियां ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट में फेल हो जाती है, उन्हें गाड़ियों के सेंट्रल डेटाबेस 'वाहन' से डी-रजिस्टर कर दिया जाएगा। सरकार इस पॉलिसी को लॉन्च करने की पूरी तैयारी में तो है, लेकिन अभी सरकार के सामने इसे लागू करने कि लिए सबसे बड़ी चुनौती इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी 25 में से सिर्फ 7 ऑटोमेटिक फिटनेस टेस्ट सेंटर काम कर रहे हैं। वहीं सिर्फ दो ऑथराइज स्क्रैपिंग सेंटर हैं, जिनमें से एक नोएडा में है।

बादाम से मिलेगी विटामिन ई की खुराक

इंदौर। आईपीटी नेटवर्क

आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर दाग-धब्बे , झुर्रियां, मुंहासे, चेहरे की असामान्य रंगत, त्वचा से जुड़ी ऐसी समस्यांएं होती हैं, जो बिन बुलाये भी चली आती हैं! इससे बचने का कोई रास्तां तो नहीं है, लेकिन हां कुछ जरूरी एहतियात इसकी गति को कम जरूर कर सकती हैं। सालों से हम जवां दिखने और स्वकस्थक रहने के नायाब लेकिन नैचुरल तरीके ढूंढ रहे हैं। यहां तीन आसान टिप्सत दिये गये हैं, जिसकी मदद से स्किन को सेहतमंद बनाये रखने में मदद मिल सकती है:

अपनी स्किन को दें विटामिन ई की खुराक

हर मौसम में स्किन से जुड़ी कई सारी समस्या ओं में विटामिन ई को काफी लाभकारी माना गया है। विटामिन ई का डोज नर्व्स को मजबूत बनाता है और स्किन को अंदर से पोषण देता है। सबसे अच्छीफ बात है कि आपको अपने खाने में अलग से विटामिन ई का सप्लीतमेंट लेने की जरूरत नहीं है। बादाम जैसी खाने की चीजों में हेल्दीन फैट्स और विटामिन ई (अल्फा -टोकोफेरॉल) होते हैं, जिनमें एंटी-एंजिंग के गुण पाये गये हैं। इससे स्किन की सेहत को फायदा मिल सकता है। अपने ब्यूटी रीजिम में रोजाना बादाम खाने की आदत डालें। चाहे आप घर पर हों, काम पर या फिर सफर कर रहे हों,बादाम कभी भी कहीं भी खाया जा सकता है।

अपनी स्किन को मॉइश्च राइज करें

हर दिन स्किन को मॉइश्चयराइज करने से अत्यभधिक सूखेपन या तैलीयपन होने की आशंका कम हो सकती है। दोनों ही स्थितियां स्किन के लिये नुकसानदायक हैं और इससे एक्नेस जैसी त्वपचा की आम समस्यात हो सकती है। साथ ही यह खुजली पैदा करने वाले कारणों को रोकने में भी मदद कर सकता है। हालांकि, मॉइश्च राइजर का चुनाव करने के दौरान अपनी स्किन का प्रकार और मौसम को ध्याकन में रखना बहुत जरूरी है। मॉइश्चाराइजर का इस्ते माल करने के अलावा, पर्याप्तस मात्रा में पानी पीने से भी आपकी स्किन को नमी देने में मदद मिलती है, इसकी पूर्ति भी शरीर के अंदर से होती है!

नियमित रूप से एक्सरफोलिएट करें

नैचुरल स्किनकेयर की दिनचर्या में सबसे अच्छीक चीज होगी, नियमित रूप से एक्सपफोलिएशन को शामिल करना। एक्सिफोलिएशन एक्ने के दाग-धब्बों, बेजान त्वसचा, ब्लैनकहेड्स और त्वइचा से जुड़ी कई अन्य समस्यासओं में बहुत कारगर होता है। एक आम और बेहतर बॉडी एक्सगफोलिएशन रूटीन के लिये अपने रेग्युसलर बॉडी क्लीजिर के साथ नैचुरल ब्रिसल वाले ब्रश, एक्सफोलिएटिंग ग्लकव या लूफा का प्रयोग करें। हफ्ते में दो या तीन बार अपनी स्किन को एक्स फोलिएट करें। इससे आपकी त्वसचा बेहतर हो जायेगी, उसे ज्यादा जोर से रगड़ने की जरूरत नहीं होती!

भारतीय बाजार में फ्रेंच कार Citroen C5 Aircross की एंट्री, डीटेल

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

फ्रेंच कंपनी Citroen ने अपनी C5 Aircross भारत में पेश कर दी है। इस कार का ऑफिशल लॉन्च मार्च 2021 में होगा। इस कार का प्रॉडक्शन भी भारत में शुरू हो चुका है। भारत में इस कार को सेगमेंट में कड़ी टक्कर मिलेगी।

इन कारों से होगी टक्कर

भारत में लॉन्च होने के बाद इस कार की टक्कर Hyundai Tucson और Jeep Compass से होगी। शुरुआती दौर में यह कार CKD यानी कम्प्लीटली नॉक डाउन यूनिट्स के तौर पर इंपोर्ट की जाएगी।

कितनी होगी कीमत ?

इस फ्रेंच कार की कीमत का खुलासा तो अभी नहीं हुआ है मगर माना जा रहा है कि इस कार की कीमत 30 लाख रुपये तक हो सकती है। यह कार एक फुली लोडेड सिंगल वेरियंट में आने वाली है।

इंजन और पावर

C5 एयरक्रॉस में पावर और परफॉर्मेंस की बात करें तो इस कार में 2.0 लीटर टर्बोचार्ज्ड डीजल इंजन दिया गया है जो 180bhp की टॉप पावर जेनेरेट करता है। कार में 8 स्पीड टॉर्क कन्वर्टर दिया गया है। Citroen C5 Aircross SUV का पिछले साल तमिलनाडु के तिरुवल्लूर स्थित प्लांट में प्रोडक्शन शुरू हुआ था। दरअसल, इसे भारत में असेंबल किया जा रहा है और इसके पार्ट्स बाहर से आ रहे हैं। सिट्रोएन ने अपनी पहली एसयूवी को भारत के 10 प्रमुख शहरों में बेचने का प्लान बनाया है और इसके लिए La Maison Citroen कॉन्सेप्ट पर इन शहरों में शोरूम खोले जाएंगे।

चीनी उत्पादन अक्टूबर-जनवरी के दौरान 25.37 प्रतिशत बढ़कर 176.8 लाख टन हुआ: इस्मा

नयी दिल्ली। चीनी उद्योग के संगठन इस्मा ने मंगलवार को कहा कि चीनी मिलों ने गत अक्टूबर से शुरू चालू चीनी वर्ष के पहले चार महीनों में 176.8 लाख टन चीनी का उत्पादन किया, जो बीते वर्ष की इसी अवधि के मुकाबले 25.37 प्रतिशत अधिक है। इस्मा के एक बयान के मुताबिक एक साल पहले की समान अवधि में चीनी उत्पादन 141 लाख टन था। चीनी की बिक्री अक्टूबर-दिसंबर के दौरान लगभग पिछले साल के बराबर 67.5 लाख टन बताई गई है। इंडियन शुगर मिल्स एसोसिएशन (इस्मा) का अनुमान है कि 2020-21 के विपणन सत्र में कुल चीनी उत्पादन 302 लाख टन रह सकता है, जबकि वर्ष 2019-20 में यह आंकड़ा 274.2 लाख टन था। इस्मा के अनुसार मौजूदा विपणन सत्र में जनवरी तक लगभग 491 चीनी मिलें चालू थीं, जबकि एक साल पहले की समान अवधि में यह आंकड़ा 447 था। देश के प्रमुख चीनी उत्पादक राज्य उत्तर प्रदेश में उत्पादन इस साल थोड़ा कम रहा, हालांकि महाराष्ट्र में उल्लेखनीय तेजी देखने को मिली। उद्योग संगठन ने बजट में डिनेचर्ड एथिल अल्कोहल पर आयात शुल्क को 2.5 प्रतिशत से बढ़ाकर पांच प्रतिशत करने के प्रस्ताव का स्वागत किया और कहा कि इससे भारतीय चीनी उद्योग द्वारा उत्पादित घरेलू गुड़ और शराब की मांग बढ़ेगी।

बिजली खपत इस जनवरी में करीब 6 प्रतिशत बढ़ी

नयी दिल्ली। देश में बिजली खपत इस साल जनवरी में छह प्रतिशत बढ़कर तीन महीने के उच्चतम स्तर 111.43 अरब यूनिट पर पहुंच गयी। यह आर्थिक गतिविधियों में तेजी का संकेत देता है। आधिकारिक आंकड़े के अनुसार पिछले साल जनवरी में बिजली खपत 105.15 अरब यूनिट थी। इसके अलावा जनवरी 2021 में बिजली की अधिकतम मांग करीब 11 प्रतिशत बढ़कर 1,89,640 मेगावाट पहुंच गयी जे पिछले साल जनवरी में 1,70,970 मेगावाट थी। इस वर्ष तीस जनवरी को बिजली की अधिकतम मांग बढ़कर 1,89,640 मेगावाट पहुंची थी। छह महीने के बाद बिजली खपत में पिछले साल सितंबर और अक्टूबर में क्रमशः 4.5 प्रतिशत और 11.6 प्रतिशत की वृद्धि हुई थी। नवंबर 2020 में बिजली खपत की वृद्धि धीमी पड़कर 3.12 प्रतिशत रही। इसका मुख्य कारण जाड़े का जल्दी आना था। दिसंबर में बिजली खपत में करीब पांच प्रतिशत की वृद्धि हुई। विशेषज्ञों के अनुसार जनवरी में बिजली खपत में करीब छह प्रतिशत की वृद्धि और अधिकतम मांग बढ़कर 1,89,640 पहुंचना इस बात का सबूत है कि ज्यादातर आर्थिक गतिविधियां अब महामारी के पूर्व स्तर पर आ गयी हैं। उन्हें उम्मीद है कि आने वाले महीनों में बिजली मांग में वृद्धि मजबूत और स्थिर रहेगी। बिजली मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार पिछले साल जनवरी में बिजली की अधिक मांग 1,70,970 मेगावाट रही। यानी इसमें इस साल जनवरी में करीब 11 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। सरकार ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये मार्च के आखिर में 'लॉकडाउन' की घोषणा की थी। उसके कारण अप्रैल से आर्थिक गतिविधियां बाधित होने से बिजली मांग में गिरावट आयी। इससे लगातार पांच महीने अप्रैल से अगस्त तक बिजली की मांग प्रभावित रही। मांग में सितंबर के बाद सुधार आया। अधिकतम मांग में सितंबर में 1.7 प्रतिशत, अक्टूबर में 3.4 प्रतिशत, नवंबर में 3.5 प्रतिशत और दिसंबर में 7.3 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

अप्रैल-दिसंबर में अनाज का निर्यात 53 प्रतिशत बढ़कर 49,832 करोड़ रुपये पर

नयी दिल्ली। देश से अनाज का निर्यात अप्रैल-दिसंबर 2020 के दौरान सालाना आधार पर 53 प्रतिशत बढ़कर 49,832 करोड़ रुपये पर पहुंच गया है। वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों से यह जानकारी मिली है। मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि बासमती चावल का निर्यात भी 5.31 प्रतिशत बढ़कर 22,038 करोड़ रुपये का हो गया, जबकि गैर-बासमती खंड का निर्यात 122.61 प्रतिशत बढ़कर 22,856 करोड़ रुपये का हो गया। गेहूं का निर्यात बढ़कर 1,870 करोड़ रुपये का हो गया, जबकि बाजरा और मक्का जैसे अन्य अनाजों का निर्यात भी 177 प्रतिशत बढ़कर 3,067 करोड़ रुपये का हो गया। बयान में कहा गया है कि कृषि एवं प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) के तहत कुल निर्यात में अनाज की हिस्सेदारी 48.61 प्रतिशत है।

कंपनियों को EPFO में अब समय पर जमा कराना होगा कर्मचारियों का PF पार्ट

नई दिल्ली। एजेंसी

सैलरी क्लास के लिए इस बार के आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़ा ऐलान किया है। वेतनभोगियों के लिए बड़ी राहत देते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि अगर एम्प्लॉयर कर्मचारी का पीएफ योगदान देर से जमा करता है तो उसे एम्प्लॉयर को छूट में लाभ नहीं मिलेगा। वित्त मंत्री ने कर्मचारियों की परेशानी का जिक्र करते हुए कहा कि हमने यह देखा है कि कुछ नियोक्ता समय पर कर्मचारी की ओर से काटी गई पीएफ की राशि को जमा नहीं करते हैं। कंपनियां कर्मचारी के वेतन से ही पीएफ और अन्य सामाजिक सुरक्षा योजना के नाम पर राशि काटते हैं लेकिन उसे समय पर जमा नहीं करते हैं।

वित्त मंत्री की दो टूक

वित्त मंत्री ने कहा कि कंपनियों की ओर से की जाने वाली इस देरी की वजह से कर्मचारियों को

ब्याज और कमाई दोनों में नुकसान होता है, लिहाजा जो कंपनियां समय पर ईपीएफओ की राशि को जमा नहीं करती हैं उन्हें कर में छूट का लाभ नहीं दिया जाएगा। गौरतलब है कि कर्मचारियों के लिए पीएफ की स्कीम काफी लाभदायक है, इससे ना सिर्फ कर्मचारियों की सेविंग होती है बल्कि उन्हें अच्छी ब्याज दर, टैक्स में छूट आदि भी मिलता है।

किनके लिए अनिवार्य है ईपीएफ कटौती

बता दें कि पीएफ वह राशि होती है जिसे कर्मचारी को नौकरी छोड़ने के बाद या रिटायरमेंट के बाद मिलती है। यही नहीं जरूरत पड़ने पर पीएफ की राशि के कुछ हिस्से को बीच में भी निकाला जा सकता है। अगर किसी कंपनी में 20 से अधिक कर्मचारी काम करते हैं तो उसका पंजीकरण कर्मचारी भविष्य निधि संगठन मे होना अनिवार्य है। ऐसे में इन कंपनियों में कर्मचारियों को दी जाने वाली सैलरी का एक हिस्सा बतौर पीएफ काटा जाता है जिसे नौकरी छोड़ने के समय कर्मचारी को दे दिया जाता है।

क्या होता है ईपीएफ

कर्मचारी अपनी सैलरी का 12 फीसदी ईपीएफके रूप में हर महीने जमा कराते हैं और कंपनी की ओर से 12 फीसदी की राशि अतिरिक्त जमा की जाती है। इसमे से 3.67 पीसदी कर्मचारी ईपीएफ और 8.33 फीसदी ईपीएस यानि पेंशन स्कीम में जमा होती है। जिसे रिटायरमेंट के बाद किश्तों में कर्मचारी को दिया जाता है। अहम बात यह है कि पीएफ के लिए जो राशि काटी जाती है उसपर किसी भी तरह का कोई टैक्स नहीं देना होता है। इसका पूरा लाभ कर्मचारियों को दिया जाता है। इस राशि पर 8 फीसदी का ब्याज भी मिलता है।

SBI YONO के 3.45 करोड़ यूजर्स को शॉपिंग पर मिलेगा 50% तक डिस्काउंट

जानें कैसे मिलेगा फायदा..!

नई दिल्ली। आईपीटी नेटवर्क

स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के बैंकिंग एंड लाइफस्टाइल प्लेटफॉर्म योनो के यूजर्स (YONO Users) को बंपर डिस्काउंट पर शॉपिंग का मौका मिलेगा. एसबीआई ने योनो सुपर सेविंग डेज (YONO Super Saving Days) का ऐलान किया है, ? जिसमें 4 से 7 फरवरी तक योनो यूजर्स को शॉपिंग पर 50 फीसदी तक का तगड़ा डिस्काउंट (Discount Offers) मिलेगा. इसमें यूजर्स को इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्निचर, ट्रैवल, हॉस्पिटैलिटी, अमेजन पर आनलाइन शॉपिंग समेत कई कैटेगरी में छूट मिलेगी।

योनो की 100 से ज्यादा मर्चेंट्स से कार्निवाल के लिए साझेदारी

योनो के करीब 3.45 करोड़ से अधिक यूजर्स इस ऑफर का फायदा ले सकते हैं। योनो ने इसके लिए अमेजन (Amazon), ओयो (OYO), सैमसंग (Samsung) और यात्रा (Yatra) समेत 100 से ज्यादा मर्चेंट्स के साथ साझेदारी की है। योनो सुपर सेविंग डेज में ओयो के साथ होटल बुकिंग पर 50 फीसदी तक की छूट मिल सकती है। वहीं, यात्रा डॉट कॉम के साथ फ्लाइट बुकिंग पर 10 फीसदी की छूट मिलेगी. इसके अलावा सैमसंग मोबाइल और टैबलेट पर 15 फीसदी की छूट मिलेगी। वहीं, पेपरफ्राई से फर्निचर खरीदने पर 7 फीसदी अतिरिक्त छूट मिलेगी. साथ ही अमेजन से चुनिंदा कैटेगरी की खरीदारी पर 20 फीसदी तक कैशबैक मिलेगा।

योनो को 3 साल में 7.4 करोड़ बार किया गया डाउनलोड

एसबीआई के एमडी (रिटेल एंड डिजिटल बैंकिंग) सीएस सेट्टी का कहना है कि योनो सुपर सेविंग डेज के तहत ग्राहकों को खरीदारी पर अच्छे ऑफर और छूट मिलेगी। इस शॉपिंग कार्निवाल को योनो यूजर्स के लिए ही डिजाइन किया गया है। बता दें कि सिर्फ 3 साल में योनो के 7.4 करोड़ डाउनलोड हो गए हैं। वहीं, 3.45 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड यूजर्स हैं।

निर्यात में हम तेजी से कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच रहे हैं : वाणिज्य सचिव

नयी दिल्ली। देश का निर्यात तेजी से कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच रहा है। वाणिज्य सचिव अनूप वधावन ने बुधवार को यह बात कही। उन्होंने कहा कि जनवरी में देश के निर्यात में सकारात्मक वृद्धि हुई है और हम तेजी से महामारी पूर्व का स्तर हासिल करने की ओर अग्रसर हैं। वधावन ने कहा कि निर्यात के मामले में भारत नए 'मोर्चे' खोल रहा है और आज मोबाइल फोन और अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स सामान की आपूर्ति अन्य देशों को कर रहा है। वधावन ने यहां संवाददाताओं से कहा, "निर्यात रफ्तार पकड़ रहा है। हम तेजी से कोविड-19 के पूर्व के स्तर पर पहुंच रहे हैं।" वाणिज्य सचिव ने कहा कि उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना से हमारा विनिर्माण का आधार मजबूत होगा। इससे हमारा निर्यात अपनी सही क्षमता हासिल कर पाएगा। जनवरी में लगातार दूसरे महीने निर्यात में बढ़ोतरी हुई। जनवरी में निर्यात सालाना आधार पर 5.37 प्रतिशत बढ़कर 27.24 अरब डॉलर पर पहुंच गया। फार्मास्युटिकल्स और इंजीनियरिंग क्षेत्रों के अच्छे प्रदर्शन से निर्यात की स्थिति बेहतर हुई है। निर्यातित उत्पादों पर शुल्क और करों की छूट (आरओडीटीईपी) योजना के बारे में पूछे जाने पर वधावन ने कहा कि इसके लिए दरों तथा उत्पादों की पहचान का काम चल रहा है। उन्होंने कहा, "इस योजना को लेकर कार्य अग्रिम चरण में है।" इस योजना के तहत ऐसे केंद्रीय, राज्य और स्थानीय शुल्कों और करों को लौटाया जाएगा, जिनपर अभी छूट या रिफंड नहीं मिला है। यह पूछे जाने पर कि कुछ विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के सदस्यों ने भारत द्वारा कई वस्तुओं पर सीमा शुल्क बढ़ाने को लेकर चिंता जताई है, सचिव ने कहा कि सभी शुल्क दरें निर्धारित दायरे में हैं।

बजट में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये, राष्ट्रीय रेल योजना 2030 पर होगा ध्यान

नयी दिल्ली। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को 2021 के केंद्रीय बजट में रेलवे के लिए 1.10 लाख करोड़ रुपये की 'रिकॉर्ड' राशि आवंटित करने की घोषणा की, जिसमें से 1.07 लाख करोड़ रुपये पूंजीगत व्यय के लिए हैं। सीतारमण ने कहा, "भारतीय रेलवे ने भारत-2030 के लिए एक राष्ट्रीय रेल योजना तैयार की है। इस योजना का मकसद 2030 तक रेलवे प्रणाली को भविष्य के लिए तैयार करना है, ताकि उद्योग के लिए लॉजिस्टिक लागत को कम किया जा सके और मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिले।" सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2021-22 पेश करते हुए कोरोना वायरस लॉकडाउन के दौरान देशभर में आवश्यक वस्तुओं के परिवहन के लिए रेलवे द्वारा दी गई सेवाओं की सराहना की। उन्होंने कहा कि रेलवे मालगाड़ियों के अलग गलियारों के चालू होने के बाद उनका मौद्रिकरण करेगी। उन्होंने कहा, "मैं रेलवे के लिए 1,10,055 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड राशि की घोषणा कर रही हूं, जिसमें से 1,07,100 करोड़ रुपये केवल पूंजीगत व्यय के लिए हैं।" उन्होंने उम्मीद जताई कि पूर्वी और पश्चिमी माल गलियारे (ईडीएफसी और डब्ल्यूडीएफसी) जून, 2022 तक चालू हो जाएंगे। वित्त मंत्री ने यात्री सुविधाओं और सुरक्षा पर जोर देते हुए कहा कि रेलवे यात्रियों के बेहतर यात्रा अनुभव के लिए बेहतर ढंग से डिजाइन किए गए विस्टाडोम एलएचबी कोच लगाएगा। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ सुनीत शर्मा ने केंद्रीय बजट को रेलवे के लिए 'कायाकल्प' वाला बजट बताया। शर्मा ने यहां संवाददाता सम्मेलन में कहा, "यह बजट सभी बजट से अलग तरह का है। यह कायाकल्प करने वाला बजट है। रेलवे के भविष्य को ध्यान में रखकर इसे तैयार किया गया है।" उन्होंने कहा कि समय पर काम पूरा करने, समय पालन, प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल, ग्राहकों को बेहतर सेवा दिए जाने, बेहतर यात्री और माल सेवा को ध्यान में रखकर यह बजट बनाया गया है। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन के दौरान ट्रेनों की औसत गति में जबरदस्त वृद्धि हुई और मालगाड़ी की रफ्तार 23 किलोमीटर प्रति घंटा से बढ़कर 46 किलोमीटर प्रति घंटा हो गयी। शर्मा ने कहा, "भारतीय रेलवे का पूंजीगत खर्च 2,15,058 करोड़ रुपये हो गया है। इसमें 7,500 करोड़ रुपये आंतरिक संसाधन से, 1,00,258 करोड़ रुपये अतिरिक्त बजटीय संसाधन से और 1,07,100 करोड़ रुपये आम बजट में पूंजीगत खर्च आवंटन से होगा।" शर्मा ने कहा, "सकल बजटीय आवंटन 2020-21 की तुलना में 37,050 करोड़ रुपये ज्यादा है। कोविड-19 महामारी के बावजूद इसमें बढ़ोतरी की गयी है।" वित्त मंत्री द्वारा बजट संबोधन में रेखांकित राष्ट्रीय रेल योजना के बारे में शर्मा ने कहा कि रेलवे के लिए यह नीति 2050 को ध्यान में रखकर तैयार की गयी है और इसके लिए 2030 तक आधारभूत संरचना विकसित करने की जरूरत होगी। शर्मा ने कहा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और पूर्वोत्तर के क्षेत्रों के लिए सबसे ज्यादा 12,985 करोड़ रुपये खर्च का प्रावधान किया गया है। उन्होंने कहा कि 2020-21 के संशोधित पूर्वानुमान 7535 करोड़ रुपये के मुकाबले 2021-22 में 72 प्रतिशत वृद्धि की गयी है। रेलवे की भविष्य की योजनाओं के बारे में सीईओ ने कहा, "पीपीपी (सार्वजनिक-निजी क्षेत्र की भागीदारी) के तहत कम से कम 150 और निजी ट्रेनें, तेजस ट्रेनें चलेंगी, पर्यटकों के लिए विस्टा डोम कोच ट्रेनें, किफायती थर्ड एसी श्रेणी कोच, स्मार्ट कोच की व्यवस्था होगी। तापमान नियंत्रित प्रणाली, जल स्तर जांच करने की सुविधा तथा डिब्बों में ज्यादा स्थान उपलब्ध कराए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि इसरो के साथ उपग्रह के जरिए 6500 ट्रेनों की निगरानी की व्यवस्था पहले से चल रही है। वित्त मंत्री ने कहा कि रेलवे भविष्य की मालभाड़ा गलियारा परियोजनाओं - खड़गपुर से विजयवाड़ा के लिए पूर्वी तट गलियारा, भुसावल से खड़गपुर के लिए पूर्व-पश्चिम गलियारा और इटारसी से विजयवाड़ा तक उत्तर-दक्षिण गलियारे पर काम आगे बढ़ाएगी। वित्त मंत्री ने कहा, "इसके अलावा भी कुछ पहल प्रस्तावित हैं। ईडीएफसी पर 263 किलोमीटर के सोननगर-गोमो खंड को इस साल सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) में लिया जाएगा। साथ ही 274.3 किलोमीटर के गोमो-दानकुनी खंड को भी इसमें शामिल किया जाएगा।" सीतारमण ने कहा कि पहले चरण के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट बनाई जाएगी।

स्वामी/मुद्रक/प्रकाशक सचिन बंसल द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स, 13, प्रेस काम्पलेक्स, ए.बी. रोड, इंदौर से मुद्रित एवं 18, सेक्टर-डी-2, सांवेर रोड, इंडस्ट्रीयल एरिया, जिला इंदौर (म.प्र.) से प्रकाशित। संपादक- सचिन बंसल

सूचना/चेतावनी- इंडियन प्लास्ट टाइम्स अखबार के पूरे या किसी भी भाग का उपयोग, पुन: प्रकाशन, या व्यावसायिक उपयोग बिना संपादक की अनुमति के करना वर्जित है। अखबार में छपे लेख या विज्ञापन का उद्देश्य सूचना और प्रस्तुतिकरण मात्र है। अखबार किसी भी प्रकार के लेख या विज्ञापन से किसी भी संस्थान की सिफारिश या समर्थन नहीं करता है। पाठक किसी भी व्यावसायिक गतिविधि के लिए स्वविवेक से निर्णय करें। किसी भी विवाद की स्थिति में न्याय क्षेत्र इंदौर, मप्र रहेगा।